घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 17- गुरूवार 19- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड एलईटी कमांडर मोहम्मद लतीफ भट ढेर...



कुलगाम, 18 नवम्बर 2026। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर इलाके में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में बुधवार को तड़के वांछित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का कमांडर मोहम्मद लतीफ भट मारा गया। कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड मस्जिद में छिपा था। इस सफलता के बाद जवानों में खुशी का माहौल है और सीआरपीएफ के महानिदेशक ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी है। सेना की चिनार कोर्प्स ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस से मिली खास जानकारी के आधार पर बुधवार को सुबह भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (सीआरपीएफ) ने कुलगाम के जंगलपुरा इलाके में 'ऑपरेशन जंगलपुरा' शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी एक मस्जिद में छिप गया। सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा की। आतंकी लतीफ भट को मस्जिद से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 9 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने लतीफ को हथियार डालने के लिए कई बार समझाया। इसके अलावा कुलगाम के एसएसपी इनायत अली ने खुद एक लंबी वीडियो कॉल के जरिए लतीफ से बात की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सरेंडर कर देता है,तो उसकी जान बख्श दी जाएगी।

गाजियाबाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान



गाजियाबाद, 18 नवम्बर 2026। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद रहे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को आज गाजियाबाद के डासना जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सपा नेता बुधवार शाम को जेल से बाहर आए। उन्होंने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जेल से निकलते ही वह सीधे गाड़ी में बैठकर रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को अपनी कार में लेकर रामपुर के लिए निकले। इस दौरान आजम खान के समर्थक बेहद बेकाबू नजर आए। उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह गाजियाबाद के सीजीएम कोर्ट में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 50- 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा हुए। इस मामले में ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

शिवसेना ने सोनिया की किताब फाड़ी,बैन की मांग

सावरकर और मराठी अस्मिता के अपमान का आरोप वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस भी नाराज...

मुंबई,18 नवम्बर 2026। शिवसेना ने बुधवार को सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव को बैन करने की मांग की। पार्टी के नेताओं ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किताब के पन्नों को फाड़ा। शिवसेना का आरोप है कि इस किताब में वीर सावरकर और मराठी अस्मिता का अपमान किया गया है। उधर, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस ने भी इस किताब को लेकर नाराजगी जताई है। वाईएसआर कांग्रेस के तिरुपति सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति ने कहा- सोनिया गांधी वाईएसआर कांग्रेस के योगदान को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि सोनिया ने किताब में तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया। सोनिया की किताब 10 नवंबर को बाजार में बिकना शुरू हुई थी। 16 नवंबर को लॉन्च की गई।



पेज नंबर 443 पर हिंदू सुप्रीमेसिस्ट का जिक्र

इस पेज पर सावरकर को 'हिंदुत्व' विचारधारा का जनक बताया गया है। कहा गया है कि उन्होंने भारत को मुख्य रूप से 'जहां हिंदू सबसे ऊपर हैं' (हिंदू सुप्रीमेसिस्ट) के नज़रिए से देखा और संघ परिवार और बीजेपी इसी भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया कि यह झूठी कहानी फैलाने की एक चाल है।

पेज नंबर 201 पर सावरकर का जिक्र

आरएसएस की राजनीति को लेकर इंदिरा गांधी की नाराजगी आजादी की लड़ाई के समय से ही थी। जब कांग्रेस के नेता अंग्रेजों की मार झेल रहे थे और जेल जा रहे थे, तब आरएसएस के बड़े विचारक विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के सामने दया याचिकाएं लिख रहे थे। आरएसएस के कुछ सदस्य अंग्रेज अधिकारियों के लिए मुखबिरी भी करते थे। आरएसएस, कांग्रेस और उसकी विचारधारा को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट मानता था। इस सोच में दूसरे धर्मों के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। आरएसएस के बड़े विचारकों ने अपनी किताबों और भाषणों में हिटलर और अल्पसंख्यकों को लेकर उसकी नीतियों की तारीफ की थी। इंदिरा गांधी को डर था कि ऐसी विचारधारा देश की एकता के लिए खतरा बन सकती है। इमरजेंसी लगाने से पहले इंदिरा गांधी के मन में यह सवाल था कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए या देश को सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी ताकतों से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए।

राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस को मजबूत किया

वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति ने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में वाईएस राजशेखर रेड्डी (वाईएसआर) के योगदान का जिक्र क्यों नहीं किया। वाईएसआर ने पदयात्रा के जरिए आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया था। उनकी वजह से 2004 और 2009 में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और केंद्र में यूपीए सरकार बनाने में भी मदद मिली।

राहुल अमेरिका में बोले-भारत आर्थिक संकट की कगार पर,बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम भी बड़ी समस्या

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली,18 नवम्बर 2026। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां हैं। युवाओं में बढ़ती निराशा की मुख्य वजह यह है कि उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता। राहुल गांधी ने यह बात बुधवार को न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी के सामने कही। राहुल अमेरिका के दो दिन के दौरे पर हैं।

एसआईआर पर खर्च को लेकर सवाल

राहुल ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सामान्य अभियान से बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने कहा, 'इस अभियान में जितना पैसा खर्च किया गया, वह अनुमान से 20, 30, 40 या 50 गुना तक ज्यादा था। इतना पैसा कहां से आया। इस अभियान में खर्च की गई रकम को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना चाहिए।'



वोटों के अंतर को बताया असंभव

राहुल ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, 'अचानक 5 लाख वोटों का मार्जिन मिल जाना संभव नहीं है। चुनावी नतीजों और वोटों के आंकड़ों को लेकर हमारी पार्टी (कांग्रेस) के पास कई सवाल हैं। हमारे पास चुनावी धांधली के कई सबूत हैं। इन्हें सामने लाने के लिए हम काम कर रहे हैं।'

चुनावी व्यवस्था में सुधार को बताया जरूरी

राहुल ने कहा, 'हमारा मकसद देश की चुनावी व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करना है। चुनावी व्यवस्था को ठीक किए बिना कुछ नहीं हो सकता। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है।'

युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा

राहुल ने कहा, 'युवाओं में मौजूदा हालात को लेकर निराशा है। इनमें एक वर्ग मध्यमवर्गीय परिवारों से आता है और उसने औपचारिक शिक्षा हासिल की है। हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।

पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ बैठक

कामकाज का रिव्यू किया,11 मंत्रालयों के सचिवों ने प्रेजेंटेशन दिया



रायपुर,18 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रीपरिषद की बैठक हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री,राज्यमंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री शामिल हुए। गृह और वित्त मंत्रालय समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने इन मुद्दों पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में गरीबी कम करने के लिए सरकार की योजनाओं की तारीफ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि सरकारी योजनाएं कितनी आगे बढ़ी हैं और जोर दिया कि इनका फायदा हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए।

बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट का जिक्र हुआ

बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इस दौरान अत्यधिक गरीबी की दर में 90% की कमी आई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कैसे कामयाबी मिली और देश में नक्सलवाद को कैसे खत्म किया गया।

जदयू नेता के शोरूम से 40 करोड़ की लूट

बेतिया,18 नवम्बर 2026। बिहार के बेतिया में जदयू नेता राजेश कुशवाहा के गोल्ड शोरूम से करोड़ों रुपए के गहनों की लूट हुई है। तीन बाइक से आए 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी के पास हथियार थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बदमाशों ने करीब 10-15 मिनट में कीमती गहने समेटे और भाग निकले। ज्वेलरी शॉप के ऑनर और जदयू नेता राजू कुशवाहा ने बताया कि 30 से 40 करोड़ रुपए के गहने लूटे गए हैं। शोरूम में घुसते ही अपराधियों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बना लिया और सभी को एक जगह बैठा दिया। इसके बाद उनके मोबाइल छीन लिए।

एसआईआर की समयसीमा बढ़ी : झारखंड समेत सात राज्यों में अब 22 दिसंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

रांची,18 नवम्बर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। झारखंड समेत सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर के बजाय 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी। आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाई है। यह फैसला अनुपस्थित, स्थानांतरित,मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी के मतदाताओं की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है। निर्वाचन आयोग का संशोधित कार्यक्रम झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नगालैंड और हरियाणा में भी लागू होगा। आयोग ने इन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 22 दिसंबर तय की है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आयोग की नई समयसारिणी के मुताबिक, एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्र तैयार करने और उनकी छपाई का काम 18 नवंबर तक पूरा कर लिया गया है।



साय कैबिनेट के फैसले...अबूझमाड़ के छात्रों को पढ़ाई के लिए 50 करोड़ मिलेंगे

पानी का बिल वसूलने पर पंचायतों को सरकार देगी 50 हजार

रायपुर,18 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार 40.98 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अगले 3 साल के लिए यह अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकार ने पानी का बिल वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में कुल 4 फैसलों को मंजूरी दी गई। राजनांदगांव में बाल सुधार गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

छोटी पंचायतों को नलजल योजना के लिए मिलेगा अनुदान

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन,संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत साल 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के जरिए नलजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव हो सकेगा।



एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगी मदद

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार यानी पानी का शुल्क जमा करना होगा। वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से ज्यादा राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो साल तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

अबूझमाड़ के कॉलेज को तीन साल में मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपए : कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल का अनुदान देने का फैसला लिया है। यह कॉलेज रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से संचालित किया जाता है। इसके संचालन और भवन सहित अन्य सुविधाओं के विकास के लिए तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के तय नियमों में छूट देने की मंजूरी भी दी गई है। इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

राजनांदगांव में बाल सुधार गृह के लिए जमीन आवंटित होगी

कैबिनेट ने राजनांदगांव में बाल सुधार गृह भवन बनाने के लिए महिला-बाल विकास विभाग को जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी। नया भवन बनने से कानून से जुड़े मामलों में शामिल बच्चों के रहने, देखभाल, परामर्श, पढ़ाई और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर होंगी।

राजनांदगांव में बनेगा शिक्षा मंडल का संभागीय दफ्तर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी। इस कार्यालय के शुरू होने से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल-कॉलेजों को मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

महादेव सट्टा केस,शुभम सोनी के खिलाफ वारंट जारी

भूपेश बघेल को 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी देने का किया था दावा,आज सौरभ चंद्राकर की पेशी

रायपुर,18 नवम्बर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में उसे ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अलग-अलग कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उससे दोबारा पूछताछ के लिए कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है।

वहीं, इस केस की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों तक पहुंचने की खबर है। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वहीं, इस मामले में फरार चल रहे शुभम सोनी के खिलाफ ईडी की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया है। शुभम सोनी नवंबर 2023 में एक वीडियो जारी कर चर्चा में आया था। उसने खुद को महादेव ऐप का असली मालिक बताया था। उसका दावा था कि साल 2021 में भिलाई में इस ऐप की शुरुआत की गई थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर वह दुबई गया था और प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। हालांकि, ये शुभम सोनी की ओर से लगाए गए आरोप थे। ईडी के अधिकारियों ने सौरभ से उसके सहयोगियों के बयानों, डिजिटल डेटा और विदेश में मौजूद कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सट्टे से हासिल रकम किस रास्ते से विदेश पहुंची और इस नेटवर्क में किन लोगों की क्या भूमिका रही। ईडी की जांच में अब तक करीब 190 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है।



रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त,3 महिलाएं अरेस्ट

5-10 लाख में बेचते,हैदराबाद-गुजरात तक नेटवर्क,ओडिशा की महिला को बंधक बनाया था

रायपुर,18 नवम्बर 2026। रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि, महिलाओं ने ओडिशा की एक गर्भवती महिला को फ्री में डिलीवरी और इलाज का झांसा देकर रायपुर बुलाया। डिलीवरी के बाद उसके नवजात बच्चे को बेचने की कोशिश की और महिला को बच्चे समेत बंधक बना लिया। महिला की शिकायत पर आजाद चौक थाने में स्नढ्ढक्रदर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के 15 से 20 नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने की आशंका। जांच में 5-6 लोगों के सिंडिकेट की आशंका जताई जा रही है। आरोपी गरीब परिवारों की महिलाओं और अवैध संबंधों के चलते गर्भवती हुई महिलाओं को निशाना बनाती थीं। उन्हें फ्री डिलीवरी और इलाज कराने का झांसा देकर नवजात बच्चों को अपने कब्जे में ले लेती थीं। पुलिस के मुताबिक,गिरोह का नेटवर्क ओडिशा,हैदराबाद और अहमदाबाद समेत देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था। शुरुआती जांच में नवजात बच्चों को कमीशन लेकर 5 से 10 लाख रुपए तक में बेचने का खुलासा हुआ है।



संपादकीय

खतरा हैं हर पक्ष के अतिवादी

एक समय माओवादियों से त्रस्त रहे बस्तर में अर्धसैनिक बलों के साथ दीवाली मनाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद से मुक्ति दिलाने में सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए आगाह भी किया कि यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं,क्योंकि दिमागी नक्सलियों ने अन्य अनेक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि आज भी वे देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और हमें इनकी पहचान करनी होगी, इन्हें परास्त करना होगा और राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा। मोदी के इन शब्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि भारत का लोकतांत्रिक संविधान महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित देश की आकांक्षाओं का प्रतीक है और इन आकांक्षाओं में सर्वप्रमुख आकांक्षा यही थी कि सभी भारतीय विशेषकर गरीब,वंचित और हाशिए के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के साथ सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। भारतीय समाज पारंपरिक रूप में कुछ सामंती स्वरूप का रहा,पर संविधान ने उसके आधुनिकीकरण की राह तैयार की। संविधान में उसके दायरे के भीतर या बाहर देश में बदलाव लाने के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले किसी भी समूह के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए,जिन भी तत्वों ने अति-वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बंदूक उठाई,उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उनका मुकाबला करना अनिवार्य था। यह संतोषजनक है कि मोदी सरकार में माओवादी हिंसा के विरुद्ध मुहिम को सफलता मिली। माओवादी हिंसा के उन्मूलन में सुरक्षा बलों के शौर्य और मोदी सरकार की दृढ़ता को स्वीकार कर उन्हें श्रेय दिया ही जाना चाहिए। जिस तरह हिंसा का समर्थन करने वाले धुर वामपंथी संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हैं,ठीक उसी तरह समाज और राजनीति में अतिवादी विचार थोपने वाले धुर दक्षिणपंथी भी संविधान की भावना से विमुख होते हैं। हमारा संविधान एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज है और यही सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। संविधान ने इस पहलू को स्वीकार किया कि भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने ऐतिहासिक भेदभाव का सामना किया है। इसीलिए उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसने अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। ऐसे में जो धुर दक्षिणपंथी ऊंच-नीच पर आधारित पुराने समाज की ओर लौटने में यकीन रखते हैं,उनके लिए भी लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य में कोई स्थान नहीं। धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ दोनों के अतिवादी कृत्य संविधान के अनुरूप नहीं हैं। धुर वामपंथी जहां क्रांति लाने के लिए हिंसक बदलाव के पैरोकार हैं,वहीं धुर दक्षिणपंथी सामाजिक क्षेत्र सहित लगभग सभी क्षेत्रों में अतीत की ओर देखते हैं। हिंसा उन सभी आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है, जिनका संविधान प्रतिनिधित्व करता है। आस्था,समुदाय और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले कृत्य भी सीधे तौर पर संविधान के विरुद्ध हैं।

खुले में शौच से मुक्ति : मानवीय गरिमा एवं निजता के लिए आवश्यक पहल



प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा,उत्तरप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

हमें यदि किसी व्यक्ति या समाज की सोच एवं मानवीय दृष्टि का आकलन करना हो तो शिक्षा,स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सार्वजनिक उपलब्धता एवं आमजन की पहुंच को समझना होगा। इस त्रिकोण की शिक्षा एवं स्वच्छता की आधार रेखा से स्वास्थ्य, स्वावलंबन,सम्मान एवं समुत्कर्ष का वर्गाकार फलक निर्मित होता है,जिस पर सुमधुर सुवासित जीवन के सुमन खिलते हैं। स्वच्छता को भारतीय वांग्मय में सर्वोपरि रखते हुए देवताओं की प्रसन्नता का हेतु बताया गया है। संत गाडगे बाबा,राष्ट्रसंत तुकडो जी,महात्मा गांधी, विनोबा भावे प्रभृति अनेकानेक महापुरुषों ने व्यक्तिगत जीवन एवं परिवेश में स्वच्छता का महत्व अपने आचरण से सिद्ध कर समाज के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत किया है। खुले में शौच जाना स्वच्छ परिवेश की रचना में एक बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित होता है। यह न केवल वातावरण को प्रदूषित-कलुषित करता है बल्कि रोगों के फैलाव का माध्यम भी बनता है। खुले में शौच जाना न केवल मानवीय गरिमा, सम्मान एवं निजता पर एक गम्भीर संकट है,अपितु सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति भी है। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए तो खुले में शौच जाना हिंसा एवं बलात्कार का कारण भी बनता है। स्वच्छता को अपनाने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 नवम्बर को विश्व शौचालय दिवस मनाना स्वच्छता संकट के प्रति वैश्विक जन-जागरूकता एवं सुरक्षित स्वच्छता कार्यों एवं संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास है ताकि रोग-शोक मुक्त परिवेश की सर्जना हो सके। विश्व शौचालय दिवस पर प्रत्येक वर्ष थीम आधारित आयोजन होते हैं। वर्ष 2026 की थीम है - सुरक्षित शौचालय,समान भविष्य। यह थीम स्वच्छता और लैंगिक समानता के सम्बंध में महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान, मर्यादा एवं गरिमा बनाये रखने का संदेश देते हुए उन्हें बिना किसी क्षति एवं बाधा के स्कूल एवं कार्यालय जा सकने,दैनंदिन कार्य निसंकोच एवं सुगमता पूर्वक कर सकने तथा सामाजिक उत्सवों में सहज सहभागिता कर सकने हेतु प्रेरित एवं सशक्त करता है।

स्वच्छता मानव जीवन के लिए एक अत्यावश्यक व्यवहार है। स्वच्छता से मन को शांति मिलती है और तन को स्वास्थ्य-सुख। स्वच्छता का आचरण व्यक्ति एवं परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। जहां स्वच्छता है,वहां सुख,शांति एवं समे द्धि का वास है,वहां प्रेम-सद्भाव,मधुरता एवं आत्मीयता का



निर्मल निर्झर प्रवहमान होता है। स्वच्छता व्यक्ति के जीवन से कलुषता,कुभाव, कुटिलता और कुसंगति के दोष-दुर्गुणों को दूर कर उसे सद्गुणों से सम्पन्न कर देती है। स्वच्छता के महत्व को श्रीमद् भागवतगीता तथा रामचरित मानस में भी रेखांकित किया गया है। भारतीय दर्शन ने तो शारीरिक एवं परिवेशीय स्वच्छता से बहुत आगे बढ़कर व्यक्ति के मन,बुद्धि एवं आत्मा की निर्मलता की बात की है। जल एवं मिट्टी को अस्वच्छता को दूर करने वाला आवश्यक घटक कहा गया है, किंतु खुले में शौच जाने से जल एवं मृदा ही अस्वच्छ हैं। हवा,पानी और माटी की स्वच्छता सरकार एवं समाज की प्राथमिकता में होने चाहिए,किंतु गम्भीरता एवं उचित उद्यमता का अभाव है।

दुनिया को स्वच्छ बनाये रखने की दिशा में विश्व शौचालय संगठन ने सर्वप्रथम वर्ष 2001 में 19 अक्टूबर को विश्व शौचालय दिवस मना कर पहल की थी और दुनिया का ध्यान स्वच्छता संकट की ओर खींचा था। आगे 24 जुलाई,2013 को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रस्ताव पारित कर 19 नवम्बर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हुए स्वच्छता के प्रति मानसिकता निर्माण करने का संकल्प लिया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सतत विकास लक्ष्य-6 अंतर्गत 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल एवं शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। किंतु यह लक्ष्य प्राप्त कर पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। कुछ आंकड़ों की बात करूं तो आज भी लगभग 3 अरब आबादी के पास पर्याप्त सुरक्षित स्वच्छता के घटक जल,शौचालय,आवास एवं पर्यावरण उपलब्ध नहीं है। एक अरब लोग खुले में शौच करने को विवश हैं, जिसकी आधी से अधिक संख्या भारत में निवास करती है। खुले में शौच करना महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अत्यंत कष्टप्रद तथा स्त्री मर्यादा,निजता, सम्मान एवं सुरक्षा के लिए बड़ा संकट है। हिंसा,छेड़खानी एवं बलात्कार की घटनाएं प्रायः ऐसे मौकों पर अधिक होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2023 की रिपोर्ट सोचने को मजबूर करती है कि अस्वच्छ जल एवं गंदगी के चलते विश्व में प्रति दिन 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 1000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है,यह सरकारों एवं संस्थाओं के सम्मुख सवाल है कि उनके अधूरे प्रयास अंततः कब पूर्ण होंगे।

स्वच्छता एवं शौचालय सुविधा के सम्बंध में मैं अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय, स्नानागार और जल निकासी हेतु ढकी नालियों का प्रबंध आश्चर्य एवं गर्व की अनुभूति कराता है। उत्खनन में प्राप्त भग्नावशेष सिद्ध करते हैं कि प्राचीन काल में नगर नियोजन में स्वच्छता को कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यह तत्कालीन समाज की स्वच्छता विषयक सम्यक जीवन-दृष्टि का परिचायक है। किलों एवं महलों में भी शौचालय देखे जा सकते हैं। आधुनिक इतिहास में सन् 1878 में अंग्रेज़ों द्वारा स्वच्छता कानून लागू कर भारतीय ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में शौचालय स्थापित करने के निर्देश दिए गये थे। 2 अक्टूबर, 2014 को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम आरम्भ किया, इसके अंतर्गत सरकारी मदद से देश भर में लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-6 वर्ष 2026 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 94 तथा शहरों में 99 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध हो गई है। बड़ी संख्या में गांवों एवं शहरों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। स्वच्छता एवं शौचालय सुविधा का संदर्भ आए तो बिहार में जन्मे डॉ. बिंदेश्वर पाठक का नाम स्मरण होना स्वाभाविक है,जिन्होंने 1970 में सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स की स्थापना कर सामान्य जन के लिए न केवल सम्मानजनक शौच सुविधा उपलब्ध कराई बल्कि स्वच्छता के महत्व से परिचित करा जागरूकता का प्रसार भी किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मविभूषण उपाधि भेंट कर अभिनंदन किया।

देश में डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ता जाल



डॉ.प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

डिजिटल क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और नागरिक जीवन को नई गति दी है। आज मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे भेजना,बिलों का भुगतान करना,खरीदारी करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। यूपीआई,इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट ने वित्तीय लेन-देन को आम आदमी की पहुँच में ला दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक गंभीर चुनौती भी तेजी से उभरी है–साइबर धोखाधड़ी। तकनीक ने जहाँ आर्थिक गतिविधियों को सरल बनाया है, वहीं अपराधियों को लोगों की मेहनत की कमाई तक पहुँचने के नए रास्ते भी उपलब्ध कराए हैं। आज साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं,बल्कि आर्थिक सुरक्षा,सामाजिक विश्वास और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है।

भारत में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के पीछे कई परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार और उसके अनुपात में डिजिटल साक्षरता का विकास न हो पाना है। देश के छोटे कस्बों, गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई की पहुँच तो बढ़ी है,लेकिन बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता डिजिटल सुरक्षा के बुनियादी नियमों से परिचित नहीं हैं। वे अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं,ओटीपी साझा कर देते हैं अथवा फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों के झाँसे में आ जाते हैं। अपराधी इसी जानकारी की कमी का लाभ उठाकर बैंक खातों से धन निकाल लेते हैं। साइबर अपराध का एक खतरनाक स्वरूप फिशिंग और पहचान की धोखाधड़ी है। इसमें अपराधी बैंक अधिकारी,सरकारी कर्मचारी,पुलिसकर्मी अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान का प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते हैं। वे खाते केवाईसी अपडेट करने, बैंक खाता बंद होने,पार्सल में प्रतिबंधित वस्तु मिलने या किसी सरकारी जाँच का हवाला देकर भय और भ्रम पैदा करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी इसका सबसे चिंताजनक उदाहरण है। इसमें अपराधी स्वयं को पुलिस,सीबीआई,ईडी या अन्य जाँच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को मानसिक रूप से बंधक बना लेते हैं। गिरफ्तारी,कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपये तक वसूल लिए जाते हैं।

तकनीक के दुरुपयोग ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की सहायता से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और नकली आवाजें अब किसी व्यक्ति की पहचान की नकल करने में सक्षम हैं। अपराधी रिश्तेदार,परिचित,वरिष्ठ अधिकारी अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवाज में फोन करके आपातकालीन आर्थिक सहायता माँग सकते हैं। पहले जहाँ गलत वर्तनी वाले संदेशों और संदिग्ध ईमेल से धोखाधड़ी की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान था,वहीं अब अत्याधुनिक तकनीक ने अपराधियों के छल को अधिक विश्वसनीय बना दिया है।

एक अन्य बड़ी समस्या म्यूल बैंक खातों की है। ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग



साइबर अपराध से प्राप्त धन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कई बार बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मामलों में लोग बिना पूरी जानकारी के अपने खाते और एटीएम कार्ड दूसरों को सौंप देते हैं। अपराधी इन खातों की श्रृंखला बनाकर धन की वास्तविक पहचान और स्रोत छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क, फर्जी सिम कार्ड,नकली पहचान और सीमापार डिजिटल लेन-देन के कारण जाँच एजेंसियों के सामने भी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।

दिलचस्प बात यह है कि साइबर धोखाधड़ी केवल अपराधियों की चालाकी का परिणाम नहीं है,बल्कि कई बार संस्थागत कमजोरियाँ भी इसे बढ़ावा देती हैं। बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल ग्राहकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकती। बैंकों को संदिग्ध खातों की पहचान,मजबूत केवाईसी प्रक्रिया और असामान्य लेन-देन की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी। यदि किसी खाते में अचानक बड़ी मात्रा में धन आने-जाने लगे अथवा कम समय में कई संदिग्ध लेन-देन हों,तो बैंक की निगरानी प्रणाली को तत्काल सक्रिय होना चाहिए। विशेष रूप से म्यूल खातों की पहचान के लिए बैंकों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और समन्वय आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियामक संस्था के रूप में आरबीआई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा के कठोर मानक सुनिश्चित करने चाहिए। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, शिकायतों के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा की नियमित समीक्षा आवश्यक है। बैंकिंग संस्थानों को यह समझना होगा कि ग्राहक का विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूँजी है। यदि डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा का भरोसा कमजोर पड़ता है,तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

बैंकों के साथ-साथ दूरसंचार कंपनियों की जवाबदेही भी कम नहीं है। साइबर अपराधी फर्जी सिम कार्ड, स्पूफड कॉल और नकली मोबाइल नंबरों का उपयोग करके लोगों को निशाना बनाते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध सिम कार्डों की पहचान, फर्जी कनेक्शन पर रोक और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार की संचार साथी पहल इस दिशा में उपयोगी कदम है। इसके माध्यम से नागरिक संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन और मोबाइल फोन से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी पहलों का लाभ तभी व्यापक होगा,जब आम नागरिकों को इनके उपयोग की जानकारी भी हो। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी निर्णायक है। साइबर अपराध की प्रकृति ऐसी है कि अपराधी एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को निशाना बना सकता है और धन को तीसरे राज्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), साइबर अपराध पुलिस थानों और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। शिकायत दर्ज होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण, संदिग्ध खातों की पहचान और धन के प्रवाह का पता लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी पीड़ित की आर्थिक क्षति बढ़ा सकती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। फर्जी विज्ञापनों, नकली निवेश योजनाओं,सरकारी अधिकारियों के नाम से बनाए गए खातों और भ्रामक लिंक के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार होते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनियों को ऐसे विज्ञापनों और खातों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। शिकायत मिलने पर संदिग्ध सामग्री को हटाने तथा अपराध से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीड़ितों को राहत देने का है। वर्तमान व्यवस्था में कई बार ठगी का शिकार व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अलग-अलग संस्थानों के चक्कर काटता रहता है। जबकि साइबर धोखाधड़ी में शुरुआती कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

कलियुगी तमाशा



पाप पुण्य के खेल में जीत रहा है पाप,
विषैले इंसानों से डरके हार रहे हैं सांप,
अपने आदेशों से मुखिया गर्दन रहे हैं नाप,
संस्कारों की बातें करते आज ये खटिया छाप,
मुखौटा पहने घूम रहे हैं,जो कल तक नालायक थे,
आज बने हैं न्यायाधीश वो,जो खुद ही खलनायक थे,
झूठ के ऊंचे सिंहासनों पर,सच बैठा असहाय है,
चमचों की इस महफ़िल में अब,चापलूसी ही न्याय है,
भीतर काला मन है जिनका,बाहर उजली खादी है,
वो ही यहां सिखा रहे हैं,क्या मर्यादावादी है,
नेक इंसान तो सहमा बैठा,कोने में चुपचाप है,
और जमाने में मचे इस ग़दर का,मुखिया ही माई बाप है,
ईमान यहां बिकता बाज़ारों में,कौड़ी के भावों में,
बैठे हैं मठाधीश यहां पर,सुख की छांवों में,
जो सच बोले उस पर ये,अपनी धौंस जमाते हैं,
दूसरों की कमियां ढूंढ ढूंढ,अपनी औकात छुपाते हैं,
पर भूल गए हैं ये अभिमानी,समय बड़ा बलवान है,
आज जो सिर पर बैठे हैं,कल होना उनका अवसान है,
कर्मों का लेखा जोखा तो,हर एक को भुगतना पड़ता है,
पाप का घड़ा जब भरता है,तो पानी सिर से चढ़ता है,
पर वक़्त का पहिया घूमता है,जब ढलेगा यह अंधियारा,
टूटेगा झूठ का भ्रम यहां,चमकेगा सच का तारा,
खटिया छाप इन ठेकेदारों का,घमंड एक दिन टूटेगा,
पाप के इस भारी घड़े से,पुण्य का अमृत फूटेगा।

राजेन्द्र लाहिरी
पामगढ़, छत्तीसगढ़

बालों की सफ़ेदी,उम्र की ढलती धूप में चमकती चांदी और जीवन का सच्चा सौंदर्य

हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है,यह एक ऐसा स्वाभाविक आकर्षण है, जिससे शायद ही कोई अछूता हो। आज के इस दौर में कृत्रिमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,तक हमारे रूप-रंग को निखारने, उम्र के निशान छिपाने और एक बनावटी खूबसूरती गढ़ने के नए-नए तरीक़े तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस कृत्रिम चमक के पीछे भागते-भागते अपनी ज़मीनी हक़ीक़त से क्यों भाग रहे हैं? क्या सुंदरता वाक़ई किसी फ़िल्टर या केमिकल में बसती है?यदि सुंदरता की कोई सच्ची परिभाषा हो, तो वह किसी चेहरे का ढांचा या कोई स्थाई पैमाना नहीं है। वास्तव में,वक्त खूबसूरत है। समय का हर पड़ाव अपने साथ एक अनूठा अनुभव और अनमोल परिपक्वता लेकर आता है।सुंदरता को यदि परिभाषित किया जाए, तो जीवन का हर पल, हर आयु अपने आप में सुंदर है। उम्र के इस सफ़र में हमारा चलना,हमारा उठना-बैठना, और एक विशेष उम्र में हमारी जीवन-शैली ही हमें असली सुंदरता प्रदान करती है। वह अनुभव जो उम्र के साथ हमारे व्यक्तित्व में घुलता है,वही हमारा असली आभूषण है। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उम्र के इस सुंदर सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हम बुढ़ापे के डर से, झुर्रियों से और बालों के सफ़ेद होने से इस तरह डरते हैं जैसे यह कोई अपराध हो। हम केमिकल वाले रंगों और हेयर डाई के जरिए अपने सिर पर उम्र के निशान छिपाने की एक अंतहीन दौड़ में शामिल हैं। हम यह भूल जाते हैं कि बालों की सफ़ेदी कोई कमज़ोरी या बुढ़ापे की लाचारी नहीं है,बल्कि यह तो उस लंबे सफ़र का मेडल है जो हमने हंसते-रोते, संघर्ष करते और जीते हुए तय किया है। ज़रा रुकिए और अपने बालों की इस सफ़ेदी को क़रीब से देखिए। यह सिर्फ़ सफ़ेद बाल नहीं हैं, बल्कि यह जीवन के अनुभव की वह चांदी है जो धूप में तपकर और छांव में जीकर कुंदन बनी है।यह चांदी उन रातों की गवाही देती है जब आपने अपने परिवार के लिए जागकर मेहनत की होगी। यह उन संघर्षों की दास्तान है जिनका सामना आपने पूरी हिम्मत से किया है।यह इस बात का प्रमाण है कि आपने जीवन के उतार-चढ़ाव को बहुत क़रीब से देखा है और हर परिस्थिति का डटकर मुक़ाबला किया है। जब हम इन सफ़ेद बालों को अपनी शान मानने के बजाय इन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही अतीत, अपने ही संघर्षों और अपनी परिपक्वता से मुंह मोड़ रहे होते हैं।सुंदरता उम्र को रोकने में नहीं, बल्कि हर उम्र को पूरी गरिमा और सादगी के साथ जीने में है। कृत्रिम रूप से युवा दिखने की यह अंधी दौड़ इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें और अपने वजूद की सहजता को स्वीकार करें।बालों की यह चांदी हमें डराती नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि हमने जीवन को जिया है, भोगा है और समझा है।

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

इंदिरा गांधी : जिनके फैसलों ने बदल दी भारत की राजनीतिक तस्वीर

विश्व राजनीति में भारत की बुलंद आवाज थी इंदिरा गांधी



योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जर लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा,''आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पे ते।'' इंदिरा जी की इन गू और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पे ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता,दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर



विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक'गूंगी गुड़िया'नहीं बल्कि 'लौह महिला' हैं।बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी अलगाववादी व साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले तत्वों को नहीं पनपने दिया। ऐसे तत्वों को उन्होंने बेदर्दी से कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई।1980 में पुनः देश का शासन संभालने के बाद पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने खालिस्तान की मांग शुरू की और दूसरे देशों की शह पर अपने नापाक इरादों को सफल बनाने के लिए सिख अलगाववादियों ने भयानक नरसंहार का दौर शुरू किया तथा पंजाब में अवैध रूप से हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश की जांबाज, निडर एवं साहसी नेता इंदिरा को भला यह कैसे सहन होता,इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी पाक जगह में भी हथियारों का विशाल जखीरा इकट्ठा किया है तो उन्हें देश की एकता और अखंडता कायम रखने तथा अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पवित्र धर्मस्थल के भीतर न चाहते हुए भी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के तहत पुलिस भेजने का सख्त निर्णय लेना पड़ा। हालांकि उस वक्त स्वर्ण मंदिर के भीतर पुलिस बल भेजने के उनके फैसले की बहुत आलोचना हुई किन्तु जब स्वर्ण मंदिर से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और धार्मिक स्थल की आड़ में चल रही इस राष्ट्र विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी की सराहना भी की। उसके बाद इंदिरा ने जिस दिलेरी और दृढ़ता के साथ अलगाववादियों को रौंदा,वह एक मिसाल बन गया लेकिन अलगाव वादियों के विरूद्ध चलाए गए उनके इसी ऑपरेशन की वजह से ही वह उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई,जिन्होंने हर हाल में उनकी हत्या कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इंदिरा जी को स्वयं अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ इरादों से टस से मस न हुई और अलगाववादियों के खिलाफ अपना अभियान पहले से भी तेज कर दिया। 30 अक्तूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने अपनी हत्या का पूर्वाभास होने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा था,''देश की सेवा करते हुए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गर्व होगा। मुझे भरोसा है कि मेरे खून की एक-एक बूंद देश के विकास में योगदान देगी और देश को मजबूत एवं गतिशील बनाएगी।'' इंदिरा जी के इस भाषण के चंद घंटों बाद ही 31 अक्तूबर 1984 की सुबह करीब सवा नौ बजे उनके दो निजी अंगरक्षकों ने ही उन्ह

भाजपा सरकार जनता नहीं,कॉरपोरेट के हित में कर रही काम : सुखदेव भगत

बोले...जल,जंगल और जमीन कांग्रेस के लिए नारा नहीं,राजनीतिक प्रतिबद्धता है,सरगुजा दौरे में आदिवासियों,किसानों और आम लोगों के मुद्दों पर सरकार को घेरा...





-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार जनता के हितों के बजाय कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जशपुर से अपने दौरे की शुरुआत करने के बाद उन्होंने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए कहा कि विकास के दावों और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर है। सरकार का कामकाज ऐसा नहीं है कि उसे नंबर दिए जा सकें। जल,जंगल और जमीन कांग्रेस के लिए महज राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि आम जनता और आदिवासी समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। नियुक्ति के बाद 16 नवंबर से शुरू हुए अपने दौरे के तहत वे जशपुर,सरगुजा और सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय चौपालों में हिस्सा लेने के साथ ग्राम साल्ही पहुंचकर परसा-केंते कोयला खनन परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों से भी मुलाकात की। प्रेसवार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदिवासियों के हितों की अनदेखी कर उनकी जमीनों पर कब्जा करने और कोयला खदानें खुलवाने की कोशिश की जा रही है। फर्जी जनसभाओं और जबरिया तरीकों से आदिवासियों की सहमति दर्शाने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी अधिकारों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी।

भगत ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विधानसभा में वन क्षेत्रों में नई खदानें नहीं खोलने के संबंध में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया था,लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने उस फैसले की भावना को दरकिनार कर दिया। उन्होंने इसे आदिवासी हितों के साथ विश्वासघात बताया। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता और आंतरिक लोकतंत्र है। सभी नेता केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियानों के साथ एकजुट हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां मोदी और शाह के इर्द-गिर्द एकतरफा संवाद की व्यवस्था है,जबकि कांग्रेस में विचारों को रखने की स्वतंत्रता है।

वोट बचाओ अभियान को बूथ तक पहुंचाने की तैयारी

प्रेसवार्ता के बाद राजीव भवन में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में सुखदेव भगत ने कार्यकर्ताओं को संगठन की



मजबूती और आगामी राजनीतिक संघर्ष के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और मताधिकार की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस लड़ाई को गांव-गांव और बूथ स्तर तक ले जाएगी। उन्होंने संगठनात्मक बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब संगठन में कार्यकर्ता की सक्रियता और उसके द्वारा किया गया काम ही आगे बढ़ने का आधार बनेगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटी है,जिसमें मतदाता की स्वतंत्र पसंद और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस मंडल और बूथ स्तरीय चौपालों के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे के साथ महंगाई,शिक्षा,स्वास्थ्य,कानून व्यवस्था और धान खरीदी में कथित अनियमितताओं को जनता के बीच ले जाएगी।

राहुल गांधी के संघर्ष को आजादी की लड़ाई से जोड़ा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि देश की आजादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए कांग्रेस के पुरखों ने लंबा संघर्ष किया था। आज उसी संघर्ष से हासिल हुए मताधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुलेआम वोट के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इसी अधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। उन्होंने मौजूदा आंदोलन को आजादी के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ हुए संघर्ष की याद दिलाने वाला बताया।

राशन कार्ड,स्मार्ट मीटर और धान खरीदी पर सिंहदेव ने घेरा

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार को स्थानीय जनसमस्याओं के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी प्रक्रियाओं के नाम पर आम नागरिकों,किसानों और हितग्राहियों के अधिकार प्रभावित किए जा रहे हैं। उन्होंने राशन कार्ड विलोपन,भारी बिजली बिल और धान खरीदी में कथित मनमानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सिंहदेव ने कहा कि त्योहारों के ठीक पहले डिजिटलीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में राशन कार्डधारियों को उनके खाद्यान्न अधिकार से वंचित किया गया। एग्रीस्टैक पंजीयन के नाम पर पात्र किसानों के रकबे शून्य घोषित कर उन्हें अपात्र किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। वहीं स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं पर अनाप-शनाप बिजली बिल का बोझ बढ़ने की शिकायतें हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार का ध्यान आम नागरिकों की समस्याओं के बजाय सत्ता और वोट के समीकरणों पर केंद्रित हो जाए,तब जनता के बुनियादी सवाल पीछे छूट जाते हैं।

बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे...

इस दौरान जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता,जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष,बूथ लेवल एजेंट और विभिन्न स्तरों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम में गरिमामय रूप से मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस समारोह

जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास और बलिदान देश के लिए सदैव प्रेरणास्रोत : सांसद चिंतामणि महाराज

शहीद परिवार एवं समाज प्रमुखों का हुआ सम्मान,जनजातीय विकास प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र







-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बुधवार को अम्बिकापुर के राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज शामिल हुए।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस हमारे जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और वीरता को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है। जनजातीय समाज ने देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरगुजा के राजनीतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा,लरंग साय,गहिरा गुरु,माता राजमोहिनी देवी,वीर नारायण सिंह जैसे महापुरुष समाज के गौरव हैं। उन्होंने कहा जनजातीय समाज एकजुट रहें तथा महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखें । लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा जनजातीय समाज ने अपनी परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दी है। जनजातीय महापुरुषों के योगदान को स्मरण करते हुए हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और समाज की उन्नति के साथ सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति,परंपराओं एवं विरासत के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया तथा कहा कि इनके संरक्षण और संवर्धन की विशेष आवश्यकता है, हम सभी को मिलकर इस ओर कार्य करना होगा। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा कि देश की आजादी और संस्कृति के संरक्षण में आदिवासी समुदाय का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिवस आदिवासी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं की उपलब्धियों को याद करने तथा आदिवासी नायक-नायिकाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने आकर्षक पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति देकर समारोह को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। इस दौरान जनजातीय विकास प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही,कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समाज के शहीद परिवारों एवं समाज प्रमुखों का विशेष सम्मान किया गया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं एवं लोक नृत्य कलाकारों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देव नारायण यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत सदस्य श्री विजय अग्रवाल,जिला पंचायत सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव,स्थानीय जनप्रतिनिधी,अधिकारी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

जनजातीय विकास प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

समारोह में जिला स्तरीय जनजातीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई,जिसमें जनजातीय समाज की समृद्ध कला,संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में क्राफ्ट, हस्तशिल्प,पारंपरिक व्यंजन,वाद्य यंत्र,पारंपरिक रंग,शौर्य गाथाएं,औषधीय ज्ञान एवं पुस्तक मेले के माध्यम से जनजातीय विरासत की विविध झलक प्रस्तुत की गई।

लोक नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता कलाकार हुए पुरस्कृत

कार्यक्रम में लोक नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता कलाकार पुरस्कृत हुए। उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र लोक नृत्य महोत्सव (करमा महोत्सव) प्रतियोगिता में विकासखण्ड लखनपुर के जय शिव शरदा करमा पार्टी परसोड़ीकला को प्रथम स्थान,विकासखण्ड मैनपाट के सुपर स्टार एक्सप्रेस करमा समिति ग्राम पंचायत डांगबुड़ा को द्वितीय स्थान एवं विकासखण्ड अम्बिकापुर के ग्राम गोर्रापारा करमा दल ग्राम पंचायत रामपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव प्रतियोगिता में विकासखण्ड बतौली के खुशबु करमा नृत्य दल ग्राम पंचायत नकना को प्रथम स्थान,विकासखण्ड मैनपाट के करमा नृत्य दल ग्राम पटेलपारा ग्राम पंचायत डांगबुड़ा को द्वितीय स्थान एवं विकासखण्ड अम्बिकापुर के शिवशक्ति करमा नृत्य दल द्वारा ग्राम पंचायत मेण्ड्राखुर्द ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सहायक प्रोग्रामर और लेखापाल के संविदा पदों के लिए कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 25 नवंबर को

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। अम्बिकापुर 18 नवम्बर 2026/ विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM G) के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर (संविदा) और लेखापाल (संविदा) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पदवार वरीयता सूची जारी कर दी गई है ।

प्रकाशित वरीयता सूची के अनुसार, सहायक प्रोग्रामर (संविदा) के 2 अनारक्षित पदों के लिए 14 अभ्यर्थियों और लेखापाल (संविदा) के 7 पदों (अन्य पिछड़ा वर्ग-1, अनुसूचित जाति-1, अनुसूचित जनजाति-2) के लिए 35 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया गया है। कुल 49 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे ।

यह कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 25 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से स्थानीय शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज, गांधी चैक, अम्बिकापुर में आयोजित की जाएगी ।

सभी संबंधित अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षा के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के परीक्षण और सत्यापन के बाद ही कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी ।सभी संबंधित अभ्यर्थियों को उनके निवास पते पर सूचना पत्र भेजा जा रहा है। यदि किसी कारणवश सूचना पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो इसे व्यक्तिगत सूचना मानकर परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहने पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in तथा सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

स्कूलों में खराब परीक्षा परिणाम पर प्राचार्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी ने ली समीक्षा बैठक,नवंबर तक कोर्स पूरा कराने और कमजोर बच्चों का नियमित रिवीजन कराने पर जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर सरगुजा के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता,परीक्षा परिणाम,विद्यार्थियों की उपस्थिति और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र बच्चों को अधिक से अधिक निःशुल्क प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए। पिछले वर्ष खराब परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों की समीक्षा करते हुए संबंधित प्राचार्यों को नोटिस जारी करने कहा गया। साथ ही इस वर्ष बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए कार्ययोजना तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। त्रैमासिक परीक्षा परिणामों पर चर्चा करते हुए कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस जारी करने तथा बच्चों को नियमित लेखन अभ्यास और रिवीजन कराने कहा गया। सभी प्राचार्यों को नवंबर तक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरा कराने के निर्देश दिए गए, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।



निर्माण कार्य में लापरवाही पर होगी कार्रवाई : बैठक में स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल शुरू कराने और किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य अधूरा नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों से नियमित समन्वय करने कहा गया। वहीं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, शिक्षकों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने तथा अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

शत-प्रतिशत पंजीयन और उपस्थिति पर जोर : अधिकारियों को यूडीआईएसई और अपार से संबंधित कार्यों में तेजी लाने, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन और उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया। सेवा पुस्तिका का संधारण एवं सत्यापन, छात्रवृत्ति के लिए सभी बच्चों का पंजीयन और सततवार शिक्षकों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों और छात्रावासों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली भरने, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए नीट और जेईई ऑनलाइन कोचिंग को प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों को इसका लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।

सरगुजा को कुष्ठ मुक्त बनाने का महाभियान,ग्राम सलका में लगा विशेष स्वास्थ्य शिविर,327 ग्रामीणों की हुई जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के उद्देश्य से बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जे.एस.आर. सरूता के निर्देशानुसार एवं जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ.पी. के. सिन्हा के मार्गदर्शन में खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ ओ.पी.प्रसाद के समन्वय से विकासखंड लखनपुर ग्राम सलका में विशेष कुष्ठ जांच शिविर आयोजित की गई। शिविर में स्वयं संभागीय कार्यक्रम अधिकारी जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ.पी. के. सिन्हा (चर्म रोग विशेषज्ञ) के द्वारा विशेष रूप से ओपीडी सेवाएं दी गई, शिविर में 327 व्यक्तियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ विशेष रूप से कुष्ठ जांच किया गया। कुष्ठ पॉजिटिव मरीजों को अपने सामने कुष्ठ की सुपरवाइजरी डोज खिलाया गया एवं उनके परिवार को सिंगल डोज रिफामपिसीन दी गई। जिला कुष्ठ अधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में जिले के ऐसे क्षेत्र जहां कुष्ठ प्रभावित है उन क्षेत्रों में लगातार शिविर लगाकर कुष्ठ के मरीजों की पहचान की जायेगी एवं ऐसे मरीज जिनको दिव्यांगता हो चुकी है और उन्हें सर्जरी कर ठीक किया जा सकता है उन्हें अगले माह सर्जरी कराया जाएगा। शिविर में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ वी सी पैकरा, जिला कुष्ठ सलाहकार सुरजीत कुशवाहा, सरपंच धीरेन्द्र सिंह, उपसरपंच गुलावती गुप्ता, बीपीएम साधना लकड़ा, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. एल एस मरकाम, फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. ऋतु सिंह सहित विकासखंड लखनपुर के सेक्टर लहपहटरा के समस्त स्वास्थ्य अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित थे।

30 से 60 साल से काबिज बंगाली विस्थापित परिवारों को मिले भूमिस्वामी पट्टा

पुनर्वास स्वाभिमान समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,वारिसों को भी भूमि पर अधिकार देने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



बंगाली पुनर्वास विस्थापित परिवारों को भूमिस्वामी पट्टा देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ पुनर्वास स्वाभिमान समिति ने कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा है। समिति का कहना है कि जिले के विभिन्न गांवों में 30 से 60 वर्षों से काबिज परिवारों को अब तक भूमि का पट्टा नहीं मिला है। इससे परिवारों को अपने ही घर और जमीन पर असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। समिति के अध्यक्ष टीडी मंडल, उपाध्यक्ष आशीष विश्वास और सचिव मानस कुमार घोष सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम चठिरमा,सरगवां,सकालो, सुभाषनगर,भगवानपुर, अजिरमा और डिगमा में भारत सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा बसाए गए परिवार लंबे समय से आबंटित एवं शासकीय भूमि पर काबिज हैं। इसके बावजूद उन्हें विधिवत भूमिस्वामी पट्टा नहीं दिया गया है। समिति ने मांग की है कि सभी पुनर्वास स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। इसके लिए स्थल निरीक्षण, पंचनामा और वास्तविक कब्जे का सर्वे किया जाए। मकान,बाड़ी,बोरिंग, शौचालय,बाउंड्रीवाल और पुराने वृक्षों को आधार बनाकर कब्जे का निर्धारण किया जाए। इसके बाद आबंटन और वास्तविक कब्जे के अनुसार परिवारों को भूमिस्वामी पट्टा दिया जाए।

वारिसों को भी मिले भूमि पर अधिकार : समिति ने कहा कि पुनर्वास विभाग द्वारा आबंटित भूमि के मूल मुखिया की मृत्यु होने पर उनके वारिसों और उत्तराधिकारियों को भी वास्तविक कब्जे के अनुसार अधिकार दिया जाना चाहिए। इन जमीनों पर परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं और कृषि सहित अन्य कार्यों से आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में पट्टा नहीं मिलने से उनके सामने बेघर होने का खतरा बना हुआ है।

पुनर्वास भूमि दूसरों को देने पर जताई आपत्ति : समिति ने आरोप लगाया कि सरगुजा,सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में पुनर्वास विस्थापितों के लिए आरक्षित एवं आबंटित जमीनों को वास्तविक कब्जे की अनदेखी कर रिक्त बताया जा रहा है। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर ऐसी जमीनों का अग्रिम आधिपत्य अन्य संस्थाओं और शासकीय प्रयोजनों के लिए दिया जा रहा है। इससे वर्षों से काबिज परिवारों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में मध्यप्रदेश शासन के पुनर्वास विभाग के 11 अक्टूबर 1989 के ज्ञापन तथा तत्कालीन विधायक मदन गोपाल सिंह के 9 अप्रैल 1990 के आदेश और 16 अप्रैल 1990 के संकल्प पत्र का भी हवाला दिया गया है। समिति ने इनका उल्लेख करते हुए पुनर्वासित परिवारों को आबंटित और कब्जे वाली भूमि का भूमिस्वामी पट्टा देने की मांग दोहराई है।



- रामगढ़ की खड़ी पहाड़ी में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी
- रेडियो कॉलर लगने से अब मिलेगी पल-पल की लोकेशन
- सूरजपुर, सरगुजा और तमोर पिंगला एलीफेंट रिजर्व की संयुक्त टीम ने संभाला मोर्चा

सात दिनों की घेराबंदी,दुर्गम पहाड़ी और लगातार बदलती लोकेशन...आखिरकार काबू में आया उत्पाती कबरा हाथी

सात दिन की मशक्कत के बाद काबू में आया कबरा,अब रेडियो कॉलर से होगी निगरानी

रामगढ़ की पहाड़ी में वन विभाग का सफल ऑपरेशन,उत्पाती कबरा हाथी को लगाया रेडियो कॉलर...

जनहानि का कारण बने कबरा हाथी पर वन विभाग का शिकंजा,सात दिन बाद ट्रैंक्विलाइज करने में मिली सफलता

रामगढ़ की खड़ी पहाड़ी में वन विभाग का चुनौतीपूर्ण अभियान सफल,विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ट्रैंक्विलाइज कर लगाया रेडियो कॉलर...

अब जंगल में हाथी की हर गतिविधि पर रहेगी नजर,सूरजपुर-सरगुजा और तमोर पिंगला एलीफेंट रिजर्व की संयुक्त टीम ने दिन-रात एक कर हासिल की सफलता...

कई जनहानि की घटनाओं से दहशत का कारण बने कबरा हाथी को नियंत्रित करने में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी...

11 नवंबर को मिला आदेश,12 नवंबर से शुरू हुआ विशेष अभियान

जानकारी के अनुसार, कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने का आदेश वन विभाग को 11 नवंबर को प्राप्त हुआ था, आदेश मिलते ही विभाग ने आवश्यक तैयारियां शुरू कीं और 12 नवंबर से कुमकी हाथियों की सहायता से कबरा की तलाश के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया, सूरजपुर, सरगुजा और तमोर पिंगला एलीफेंट रिजर्व की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सक्रिय होकर हाथी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की, अभियान की शुरुआत से ही टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथी की लोकेशन का लगातार बदलना था, जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वन अमले को लगातार अलग-अलग स्थानों पर निगरानी रखनी पड़ रही थी, दुर्गम भूभाग के कारण अभियान को अंजाम देना आसान नहीं था,कई बार हाथी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए टीम को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। इसके बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभियान को जारी रखा, कुमकी हाथियों की सहायता से तलाश और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था ने अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की, टीम ने जल्दबाजी के बजाय अनुकूल अवसर और सुरक्षित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी, अंततः रामगढ़ की खड़ी पहाड़ी में कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने का अवसर मिला और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई।


सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक बना अभिशाप
पांच साल में 179 लोगों की मौत
अकेले कबरा हाथी ने छह महीने में ली 16 लोगों की जान
23 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 737 मौतें
जंगल का राजा और गांव की जिंदगी खतरे में, हाथियों के आतंक में उजड़ रहे परिवार
हाथियों के खौफ में जी रहा सरगुजा,मौतों का आंकड़ा बढ़ा लेकिन स्थायी समाधान अब भी दूर


कबरा कान हाथी का
फिर खूनी तांडव
एक और महिला की मौत, दूसरी का पैर टूटा
एक महीने में 18 लोगों की जान ले चुका है हाथी
खूंखार के कहर अब सूरजपुर के उदयपुर रोड में आतंक
अब ट्रैंकुलाइज कर लगाया जाएगा सैटेलाइट रेडियो कॉलर
18 जिंदगियां निगल चुका कबरा कान,फिर मचाया खूनी तांडव!
सूरजपुर से उदयपुर तक मौत का सफर! कबरा कान ने फिर ली महिला की जान...
18 जिंदगियां निगल चुका कबरा कान,अब ट्रैंकुलाइज कर लगेगा रेडियो कॉलर

सीसीएफ वाइल्डलाइफ डॉ. प्रणय मिश्रा के नेतृत्व में चला विशेष अभियान,अब तकनीक के सहारे मानव-हाथी संघर्ष रोकने की होगी बड़ी परीक्षा

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर और सरगुजा अंचल में लंबे समय से दहशत का पर्याय बने उत्पाती जंगली हाथी 'कबरा' को आखिरकार वन विभाग की संयुक्त टीम ने सात दिनों के अथक प्रयास,रणनीतिक निगरानी और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंक्विलाइज करने में सफलता हासिल कर ली,रामगढ़ की दुर्गम और खड़ी पहाड़ी में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में हाथी को सुरक्षित तरीके से बेहोश किया गया और उसके शरीर पर रेडियो कॉलर लगाया गया,इस सफलता के साथ ही वन विभाग को अब कबरा हाथी की गतिविधियों और उसके विचरण क्षेत्र की नियमित जानकारी मिल सकेगी,लंबे समय से हाथी की बदलती लोकेशन के कारण जिस पर प्रभावी निगरानी रखना चुनौती बना हुआ था,अब रेडियो कॉलर की मदद से उसकी आवाजाही पर नजर रखना पहले की तुलना में आसान होगा।

कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज करना वन विभाग के लिए केवल एक तकनीकी कार्रवाई नहीं, बल्कि मानव-हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान था,इस हाथी से जुड़ी पूर्व की जनहानि की घटनाओं के कारण सूरजपुर और सरगुजा अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ था,हाथी की लगातार बदलती लोकेशन,घने जंगल, दुर्गम पहाड़ी रास्ते और अनुकूल अवसर का इंतजार अभियान को लगातार कठिन बना रहे थे,ऐसे में वन विभाग ने सूरजपुर,सरगुजा और तमोर पिंगला एलीफेंट रिजर्व की संयुक्त टीम के साथ विशेष रणनीति बनाकर अभियान शुरू किया। सात दिनों तक चले प्रयासों के बाद रामगढ़ की खड़ी पहाड़ी में टीम को सफलता मिली, इस अभियान में वरिष्ठ वन अधिकारियों का मार्गदर्शन, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तकनीकी दक्षता,कुमकी हाथियों की सहायता,ड्रोन से निगरानी और मैदानी वन अमले की लगातार सक्रियता निर्णायक रही,अब रेडियो कॉलर लगने के बाद वन विभाग के सामने अगली जिम्मेदारी इस तकनीक से मिलने वाली जानकारी के आधार पर हाथी की गतिविधियों की सतत निगरानी करना और संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में समय रहते ग्रामीणों को सतर्क करना है।

रामगढ़ की खड़ी पहाड़ी में मिली निर्णायक सफलता-रामगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ,दुर्गम और खड़ी पहाड़ी के बीच हाथी की मौजूदगी के कारण वन अमले के लिए अभियान को अंजाम देना आसान नहीं था,ऐसे क्षेत्र में हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए सावधानी,तकनीकी दक्षता और आपसी समन्वय बेहद जरूरी था,विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने हाथी को सुरक्षित तरीके से बेहोश करने की प्रक्रिया पूरी की,इसके बाद रेडियो कॉलर लगाने की कार्रवाई की गई,इस पूरी प्रक्रिया में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई,सात दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद मिली इस सफलता ने अभियान में जुटे पूरे वन अमले को बड़ी राहत दी,कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने के बाद रेडियो कॉलर लगाया जाना इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है,इससे अब वन विभाग को हाथी की गतिविधियों पर तकनीक आधारित निगरानी रखने का अवसर मिलेगा।

सीसीएफ वाइल्डलाइफ डॉ. प्रणय मिश्रा के नेतृत्व में चला अभियान-इस विशेष अभियान का नेतृत्व एवं निर्देशन सीसीएफ वाइल्डलाइफ डॉ. प्रणय मिश्रा ने किया,उनके मार्गदर्शन में सीसीएफ दिलराज प्रभाकर,सूरजपुर डीएफओ विपुल अग्रवाल,सरगुजा डीएफओ लोकनाथ पटेल तथा तमोर पिंगला एलीफेंट रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ सिंह ठाकुर ने अभियान की निगरानी की,प्रशिक्षु आईएफएस कुणाल मिश्रा सहित सूरजपुर और सरगुजा वनमंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मैदानी स्तर पर अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अभियान के दौरान अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर टीम ने समन्वित तरीके से काम किया,इस अभियान में रायपुर और बिलासपुर से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल ने भी अहम भूमिका निभाई,हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने और रेडियो कॉलर लगाने की चिकित्सकीय एवं तकनीकी प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी की गई, वन विभाग के लिए यह जरूरी था कि हाथी को नियंत्रित करने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूरी हो और रेडियो कॉलर लगाने की कार्रवाई भी सुरक्षित ढंग से संपन्न हो।

ड्रोन निगरानी से लेकर मैदानी मोर्चे तक वन अमले की सक्रियता-सात दिनों तक चले इस अभियान में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी टीम सक्रिय रही,सीसीएफ वन्यजीव डॉ. प्रणय मिश्रा, डीएफओ सूरजपुर विपुल अग्रवाल,डीएफओ सरगुजा लोकनाथ पटेल और डिप्टी डायरेक्टर एलीफेंट रिजर्व सौरभ सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु आईएफएस कुणाल मिश्रा,एसडीओ सूरजपुर संतोष पाण्डेय,एसडीओ ओड़गी अर्पित राय,एसडीओ उदयपुर सपना मुखर्जी और एसडीओ प्रतापपुर संस्कृति बारले ने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,मैदानी स्तर पर रेंजर फेकू प्रसाद चौबे, पूजा यादव, उत्तम मिश्रा,सुनीत साहू और रामनिवास दहायत सक्रिय रहे। वहीं वनपाल गिरीश बहादुर सिंह, रामबिलास सिंह,शशिकांत सिंह,मलेश्वर पैकरा,यादनंद सिंह और अशोक सिंह ने भी अभियान में योगदान दिया, हाथी की गतिविधियों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखने की जिम्मेदारी ऋतिक सोनी,राजाराम यादव,इंद्र प्रसाद पिपला,बसंत राम और आर्मो कुमार ने संभाली। इसके अलावा वनरक्षक इग्नेश बैक,अमरनाथ राजवाड़े, नंदकुमार,राजू टोप्पो,राजेश राजवाड़े,पूरण राम, अमरनाथ,विष्णु सिंह,राजेश कुजूर,सहिस कपूर, अवधेश पुरी और बृजभान सहित अन्य कर्मचारियों ने भी सक्रिय योगदान दिया,इस तरह अभियान केवल अधिकारियों के निर्देश तक सीमित नहीं रहा,बल्कि मैदानी स्तर पर वनकर्मियों की लगातार सक्रियता और अलग-अलग टीमों के बीच समन्वय ने इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रेडियो कॉलर से मिलेगी हाथी की पल-पल की लोकेशन-कबरा हाथी को रेडियो कॉलर लगाए जाने के बाद अब वन विभाग के पास उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखने का एक महत्वपूर्ण तकनीकी माध्यम उपलब्ध हो गया है,हाथी जंगल के किस हिस्से में विचरण कर रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी गतिविधियां किन क्षेत्रों के आसपास हैं,इसकी जानकारी विभाग को नियमित रूप से मिल सकेगी,अब तक हाथी की बदलती लोकेशन के कारण उसके विचरण क्षेत्र पर लगातार नजर रखना कठिन चुनौती थी,कई बार हाथी की मौजूदगी की जानकारी मिलने तक वह दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ चुका होता था,ऐसी स्थिति में वन अमले को उसकी गतिविधियों का अनुमान लगाने और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते थे, रेडियो कॉलर लगने के बाद इस समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है,सूरजपुर वनमंडलाधिकारी विपुल अग्रवाल ने बताया कि रेडियो कॉलर लगाए जाने के बाद अब कबरा हाथी की लोकेशन की नियमित जानकारी मिलती रहेगी,लोकेशन के आधार पर संबंधित वन विभाग की टीमें उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकेंगी,इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी की मौजूदगी की पूर्व जानकारी मिलने और आवश्यक सतर्कता बरतने में मदद मिलेगी,उन्होंने बताया कि विभाग अब हाथी के व्यवहार और जंगल में उसकी गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा, ताकि भविष्य में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।

जनहानि की घटनाओं के बाद ग्रामीणों को बड़ी राहत-कबरा हाथी के कारण सूरजपुर और सरगुजा अंचल में पूर्व में कई जनहानि की घटनाएं हो चुकी हैं,इस वजह से हाथी की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच चिंता और भय बना रहता था, ऐसे में उसे ट्रैंक्विलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की सफलता वन विभाग के साथ-साथ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी राहत भरी खबर है,अब हाथी की लोकेशन मिलने से वन विभाग को संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने में मदद मिल सकेगी, इससे वन अमले को भी मौके पर पहुंचने और आवश्यक सावधानी बरतने के लिए बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा,हालांकि,रेडियो कॉलर लगने का अर्थ यह नहीं है कि मानव-हाथी संघर्ष की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है, हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना,उसकी लोकेशन का सही विश्लेषण करना और समय पर सूचना संबंधित गांवों तक पहुंचाना अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, तकनीक तभी कारगर साबित होगी,जब उसके आधार पर मैदानी स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित हो।

अभियान की सफलता के बाद अब असली परीक्षा सतत् निगरानी की-कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की सफलता वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है,सात दिनों तक चले चुनौतीपूर्ण अभियान ने यह दिखाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व,विशेषज्ञों की तकनीकी दक्षता और मैदानी अमले के सामूहिक प्रयास से कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है,लेकिन इस सफलता का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा,जब रेडियो कॉलर से मिलने वाली लोकेशन का नियमित विश्लेषण हो और हाथी की गतिविधियों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते चेतावनी जारी की जाए,वन विभाग को ग्रामीणों के साथ बेहतर संवाद,सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था को भी मजबूत रखना होगा,कबरा हाथी को रेडियो कॉलर लगाए जाने से अब उसकी गतिविधियों को समझने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में एक नया रास्ता खुला है,सात दिनों की मेहनत के बाद मिली इस सफलता के बाद अब उम्मीद है कि तकनीक और मैदानी सतर्कता के समन्वय से ग्रामीणों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।

27 नवंबर को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रघुनाथनगर

कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा



-संवाददाता-

बलरामपुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का 27 नवंबर 2026 को वाड्रफनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत रघुनाथनगर में आगमन प्रस्तावित है। इसे देखते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने रघुनाथ नगर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने हेलीपैड के लिए प्रस्तावित आश्रम ग्राउंड का जायजा लिया और हेलीपैड निर्माण, सुरक्षा घेरा तथा आवागमन से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मंच व्यवस्था, अतिथियों और आमजन के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, बिजली, साउंड सिस्टम और साफ-सफाई की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती,वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य दल, एम्बुलेंस और अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन आपसी समन्वय से समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।सौरभ सिंह ठाकुर सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

लंबित अपराधों को 10 फीसदी तक सीमित करने का लक्ष्य,एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश

CCTNS 2.0 के तहत थानों को मिले 24 कंप्यूटर, 28 मोबाइल, 16 टैबलेट और 10 प्रिंटर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिले में लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने बुधवार को पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के राजपत्रित अधिकारियों और समस्त थाना-चौकी प्रभारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने जिले की कुल अपराध पेंडेंसी को 10 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य देते हुए पुराने अपराधों, लंबित चालानों, शिकायतों, मर्ग और खात्मा-खारिजी प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने को कहा। बैठक में लंबित स्थायी वारंटों की शत-प्रतिशत तामीली सुनिश्चित करने तथा पुराने चालानों को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। चोरी और नकबजनी के मामलों में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ चोरी गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी पर जोर दिया गया। गुंडा-बदमाशों की जानकारी सीआरए पोर्टल पर दर्ज करने तथा वात्सल्य और आईरेड पोर्टल पर आवश्यक जानकारियों की समयबद्ध एंट्री करने को कहा



गया। साइबर अपराधों की समीक्षा करते हुए एसएसपी ने एनसीआरपी और एमआरएम पोर्टल पर लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा म्यूल बैंक खातों से जुड़े मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। आईटी एक्ट के मामलों की प्रभावी विवेचना के लिए विशेष सेल गठित करने को भी कहा गया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट सहित अन्य कानूनों के तहत अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करने तथा प्रभावी रात्रि गश्त करने को कहा गया। एसएसपी ने सभी थाना-चौकी प्रभारियों को विजिबल पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो। बैठक में CCTNS 2.0 परियोजना के तहत थानों को आधुनिक तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। जिले को 24 कंप्यूटर, 28 मोबाइल, 16 टैबलेट और 10 प्रिंटर प्रदान किए गए हैं। इन उपकरणों के माध्यम से थानों के ऑनलाइन कार्यों और डिजिटल रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित एवं तेज बनाने का लक्ष्य है। एसएसपी ने सीसीटीएनएस पोर्टल पर नियमित अद्यतन एंट्री करने तथा IIF-1 से IIF-5 तक के प्रपत्रों की जानकारी समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए। समाधान ऐप में भी लगातार जानकारी अपडेट करने को कहा गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी, राजेश देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक बी, एसडीओपी ग्रामीण राकेश बघेल, एसडीओपी सीतापुर तुल सिंह पट्टावी, प्रशिक्षु डीएसपी निशांत गौरव कुर्रे, साइबर सेल प्रभारी सहित जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

CMYK

कांटारोली की जनचौपाल से कांग्रेस ने भरी हुंकार

जल-जंगल-जमीन की लड़ाई को तेज करने का ऐलान

सुखदेव भगत बोले...आदिवासी अधिकारों और क्षेत्र की अस्मिता की लड़ाई में कांग्रेस क्षेत्रवासियों के साथ







दीपक बैज,डॉ. चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव ने भाजपा सरकार को घेरा

तारा कोल ब्लॉक और हसदेव का मुद्दा बना जनचौपाल का केंद्र,वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के बहाने कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार

मताधिकार और संविधान की रक्षा को लेकर दिखाई राजनीतिक एकजुटता

-संवाददाता-
सूरजपुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रेमनगर विकासखंड के ग्राम कांटारोली में आयोजित विशाल जनचौपाल के जरिए कांग्रेस ने सरगुजा अंचल में जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष का बिगुल फूंका,कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत आयोजित इस जनचौपाल में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया,छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद सुखदेव भगत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आदिवासी अधिकारों, संविधान की भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया, जनचौपाल का सबसे प्रमुख मुद्दा तारा कोल ब्लॉक और हसदेव क्षेत्र में आदिवासी अधिकारों से जुड़ा रहा,नेताओं ने इसे केवल खनन अथवा जमीन का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय की संस्कृति,पहचान, आजीविका और भविष्य से जुड़ा सवाल बताया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर पार्टी क्षेत्रवासियों के साथ खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी।

बैज और सिंहदेव ने भी भाजपा सरकार को घेरा- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जनचौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए,दोनों नेताओं ने वोट बचाओ अभियान के उद्देश्य और लोकतंत्र में मताधिकार की अहमियत को प्रमुखता से रखा,उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना जरूरी है,नेताओं ने एसआईआर, कथित वोट चोरी,महंगाई,भ्रष्टाचार और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा, उन्होंने बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी समाज के सामने मौजूद सवालों और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया, इस दौरान नेताओं ने 'वोट बचाओ- देश बचाओ','सूरजपुर बचाओ','प्रेमनगर बचाओ','तारा बचाओ' और 'कांटारोली बचाओ' के नारे लगवाकर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में उत्साह भरने का प्रयास किया।

तीन दिवसीय प्रवास के दौरान कांटारोली पहुंचे प्रदेश के दिग्गज नेता- छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सांसद सुखदेव भगत अपने तीन दिवसीय सरगुजा अंचल प्रवास के दौरान कांटारोली पहुंचे,उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मोहन मरकाम और सह प्रभारी जरिता लैतफलांग सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे,कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया और अतिथियों का अभिनंदन किया, जनचौपाल में स्थानीय समस्याओं,लोकतांत्रिक अधिकारों, आदिवासी हितों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

तारा चौक पर आतिशी स्वागत, बाइक रैली के साथ पहुंचे नेता- जनचौपाल से पहले तारा चौक पर कांग्रेस नेताओं का भव्य स्वागत किया गया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह, जिला प्रभारी गुलाब कमरो,इस्माइल खान और दानिश रफीक के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज,सह प्रभारी जरिता लैतफलांग,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत,पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मोहन मरकाम का स्वागत किया गया,इसके बाद बाइक रैली और पारंपरिक शैला एवं शुग्गा नृत्य दलों की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनचौपाल स्थल कांटारोली पहुंचे,यहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह सहित इस्माइल खान,संजय डोसी, सुनील अग्रवाल,मेहंदी यादव,अरविंद यादव, अशोक जगते,तुलसी यादव,रामकुमार बंछोर, संतोष पावले और आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अतिथियों को तीर-धनुष भेंटकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।

बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस पदाधिकारी और ग्रामीण- जनचौपाल में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, डॉ. प्रेमसाय सिंह, पूर्व विधायक विनय जायसवाल, पारसनाथ राजवाड़े, भानुप्रताप सिंह, रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर, बालकृष्ण पाठक, सफी अहमद, दानिश रफीक, विंकी बाबा, सुभाष गोयल, नरेंद्र जैन, सुनील अग्रवाल, आनंद कुंवर, भगवती राजवाड़े, अखिलेश सिंह, हेमलता राजवाड़े, बबिता गुप्ता, लिली राजवाड़े, विमला सिंह, सुखमनिया जगते, आलोक साहू, रोहित कन्नौजे, विद्यासागर सिंह, नवीन जायसवाल, संजीव श्रीवास्तव, अंशुल गोयल, चंदन सिंह, जरीना सुल्ताना, अरबिना बेगम, खुशी, दिव्या तांजे, जगत आयाम, महेंद्र साहू, केबी सिंह, कवल बिहारी सिंह,प्रदीप राजवाड़े, लवकेश गुर्जर, संतोष पावले, लिवनेश सिंह, रामकुमार बंछोर, समीर सिंह, मुन्नी सिंह, सविता सिंह, कुसुमलता राजवाड़े, नरेंद्र यादव, प्रदीप साहू, गिरधारी साहू, नवल सिंह, प्रवेश गोयल, परमेश्वर राजवाड़े, पवन साहू, दिनेश राजवाड़े, बिहारी कुलदीप, संदीप शर्मा, चंद्रदत्त दुबे और चंदा सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, कांग्रेस के जिला, ब्लॉक, मंडल एवं बूथ स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुखदेव भगत का ऐलान...आदिवासियों के अधिकारों से समझौता नहीं...

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद सुखदेव भगत ने अपने संबोधन में कहा कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कांग्रेस क्षेत्रवासियों के साथ मजबूती से खड़ी है,उन्होंने भाजपा सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी करने तथा पेसा कानून और संविधान की पांचवीं अनुसूची की भावना के उल्लंघन का आरोप लगाया,भगत ने कहा कि तारा कोल ब्लॉक और हसदेव बचाओ आंदोलन केवल जमीन का मुद्दा नहीं है,यह आदिवासियों की संस्कृति,पहचान,आजीविका और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है,आदिवासी समाज का जीवन जंगल और जमीन से जुड़ा है,इसलिए उनके अधिकारों की अनदेखी कर कोई भी विकास की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती,उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों की जमीन,जंगल और अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी,केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने वोट चोरी और देश की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि सत्ता से बड़ा संविधान है और संविधान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता,कांग्रेस और राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं,उन्होंने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

तारा कोल ब्लॉक और हसदेव पर कांग्रेस का राजनीतिक संदेश

कांटारोली की जनचौपाल में तारा कोल ब्लॉक और हसदेव का मुद्दा प्रमुखता से उठना अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है,सरगुजा अंचल में आदिवासी अधिकार, वन क्षेत्र,जमीन और खनन से जुड़े सवाल लंबे समय से चर्चा के केंद्र में रहे हैं,ऐसे में कांग्रेस ने इन मुद्दों को जनचौपाल के मंच से उठाकर स्थानीय असंतोष और क्षेत्रीय सरोकारों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाने की कोशिश की,सुखदेव भगत सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का भरोसा दिलाया,हालांकि जनचौपाल में उठाए गए सवालों का वास्तविक असर आगे की राजनीतिक और जनआंदोलन की गतिविधियों पर निर्भर करेगा, फिलहाल कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह तारा और हसदेव के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी।

जनचौपाल से आगे कितनी मजबूत होगी अधिकारों की लड़ाई?

कांटारोली की जनचौपाल में कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार, तारा कोल ब्लॉक, हसदेव,मताधिकार और संविधान की रक्षा को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहराई,प्रदेश के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को व्यापक राजनीतिक स्वरूप दिया,अब देखने वाली बात यह होगी कि मंच से किए गए संघर्ष के ऐलान को कांग्रेस किस तरह जमीन पर उतारती है और स्थानीय मुद्दों पर ग्रामीणों के साथ आगे किस स्तर तक खड़ी रहती है,जनचौपाल ने यह संदेश जरूर दिया कि कांग्रेस सरगुजा अंचल में जल,जंगल और जमीन के सवाल को अपनी राजनीतिक लड़ाई का प्रमुख आधार बनाने की तैयारी में है, लेकिन इस अभियान की असली कसौटी नारों और मंचीय भाषणों से आगे बढ़कर क्षेत्रवासियों के मुद्दों पर निरंतर सक्रियता और ठोस पहल होगी।



ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर स्टाफ नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

2800 की जगह 4800 ग्रेड पे देने की मांग,मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ग्रेड पे वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले स्टाफ नर्स बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। खासकर ऑपरेशन और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे नहीं चाहते कि उनकी हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो, लेकिन लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हड़ताल के दौरान मरीजों के साथ किसी तरह की अप्रिय स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की होगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य चिकित्सक एवं पैरामेडिकल संवर्ग को छठवें वेतन आयोग के अनुरूप केंद्रीय वेतनमान का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2012 में चिकित्सा शिक्षा विभाग के गठन के बाद भी नर्सिंग संवर्ग को इससे वंचित रखा गया। पिछले 14 वर्षों से नर्सिंग कर्मचारी ग्रेड पे वेतनमान में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

2800 से बढ़ाकर 4800 ग्रेड पे करने की मांग

एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि चार वर्षीय नर्सिंग डिग्री के बावजूद कर्मचारियों को मिल रहे 2800 ग्रेड पे को बढ़ाकर 4800 किया जाए। यदि 4800 ग्रेड पे देना संभव नहीं है तो 4400 ग्रेड पे का पूर्व में तैयार प्रस्ताव ही स्वीकृत किया जाए। संगठन का कहना है कि 24 घंटे मरीजों की सेवा में जुटे नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी

एसोसिएशन की अध्यक्ष मालती सिंह और उपाध्यक्ष प्रज्ञा सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को ही मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना सरकार को दे दी गई थी। इसके बाद 16 नवंबर को भी पुनः सूचना दी गई। पूर्व में लिए गए प्रांतीय निर्णय के अनुसार 18 नवंबर से कर्मचारियों ने काम छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि तीन दिनों तक अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन करने के बाद आंदोलनकारी रायपुर जाएंगे और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे।

सूरजपुर में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी,14 घंटे से अधिक समय बाद भी कार्रवाई जारी

पीआरए ग्रुप से जुड़े ठिकानों सहित पांच स्थानों पर एक साथ दबिश, 12 गाड़ियों में पहुंचे एमपी-सीजी के करीब 25 अधिकारी-कर्मचारी

-संवाददाता-
सूरजपुर 18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है, शहर में सुबह-सुबह शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी को नौ घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई लगातार जारी है, आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें शहर के पांच ठिकानों पर एक साथ पहुंचकर दस्तावेजों,वित्तीय लेन-देन और कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं, इस कार्रवाई के दायरे में पीआरए ग्रुप से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं,अचानक हुई इस कार्रवाई से जिले के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

सुबह छह बजे 12 गाड़ियों में पहुंची टीम- जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम बुधवार सुबह करीब छह बजे लगभग 12 गाड़ियों में सवार होकर सूरजपुर पहुंची,मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 25 अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीम ने एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी,कार्रवाई इतनी सुनियोजित तरीके से की गई कि संबंधित प्रतिष्ठानों और परिसरों में जांच शुरू होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर आ सकी, इसके बाद से ही आयकर विभाग की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं।

पीआरए ग्रुप के बर्बरीक प्रोजेक्ट सहित दो मकान जांच के दायरे में- सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की कार्रवाई में पीआरए ग्रुप से जुड़े कुल तीन ठिकानों को जांच के दायरे में लिया गया है,इनमें बर्बरीक प्रोजेक्ट का कार्यालय और दो आवासीय परिसर शामिल बताए जा रहे हैं,यहां विभागीय अधिकारी कारोबार से संबंधित दस्तावेजों,आय-व्यय के ब्यौरे, वित्तीय लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की पड़ताल कर रहे हैं,जांच का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध दस्तावेजों और घोषित वित्तीय विवरणों का मिलान करना बताया जा रहा है।

नयनपुर औद्योगिक क्षेत्र की राइस मिल में भी दबिश- वहीं आयकर विभाग की कार्रवाई का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र नयनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित साकेत राइस मिल है, बताया जा रहा है कि यह राइस मिल एक बड़े भाजपा नेता के भाई से जुड़ी है,विभाग की टीम ने राइस मिल के साथ उसके मालिक के निवास पर भी पहुंचकर जांच शुरू की है, यहां भी कारोबार से संबंधित दस्तावेजों, आय-व्यय के रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, इस तरह शहर और औद्योगिक क्षेत्र के कुल पांच ठिकाने आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं।

कागजी दस्तावेज ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे- छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमें केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जा रही है, परिसरों में मौजूद कंप्यूटर, लैपटॉप, पेनड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुरक्षित कारोबारी जानकारियों को खंगाला जा रहा है,अधिकारियों द्वारा वित्तीय लेन-देन,खातों के विवरण,कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

आयकर चोरी के आरोपों के बाद कार्रवाई की चर्चा- सूत्रों के अनुसार आयकर चोरी की आशंका और आरोपों के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है,हालांकि आयकर विभाग की ओर से अब तक जांच के संबंध में कोई आधिकारिक विस्तृत जानकारी अथवा संभावित कर चोरी की राशि का खुलासा सामने नहीं आया है,फिलहाल अधिकारी सभी ठिकानों पर उपलब्ध दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल में जुटे हुए हैं।

दो से तीन दिनों तक चल सकती है जांच- कार्रवाई का दायरा,एक साथ पांच ठिकानों पर जांच और दस्तावेजों की संख्या को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई दो से तीन दिनों तक चल सकती है, हालांकि जांच कितने समय तक जारी रहेगी,यह अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की पड़ताल और सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा, फिलहाल सूरजपुर में आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर कारोबारी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं,अब सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं,विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन वित्तीय अनियमितताओं अथवा कर संबंधी गड़बड़ियों को लेकर कार्रवाई की गई और जांच में क्या तथ्य सामने आए,वही समाचार लिखे जाने तक विभाग के अधिकारी डटे हुए थे।



सीने में अचानक उठा दर्द,महिला की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के अजिरमा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली एक महिला के सीने में अचानक दर्द उठा, अस्पताल ले जाने पर जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिला के बसदेई पुलिस चैकी के ग्राम



चोपन की कमला गुप्ता पति अजय गुप्ता 44 वर्ष वर्तमान में गांधीनगर थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन अंबिकापुर में अपने पुत्र-पुत्री और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती है। 17 नवम्बर की रात को महिला सीने में अचानक दर्द होने लगा। परिजन सीने में मालिकस की पर राहत नहीं मिला तो उसे 11.30 बजे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कीटनाशक का सेवन किए अधेड़ की इलाज के दौरान मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन किए अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के रनपुर खुर्द माझापारा निवासी मृतक के पुत्र चेतन राम ने बताया कि, 17 नवम्बर को शाम करीब 7 बजे वह किराना सामान लेने के लिए दुकान में गया था, इस दौरान चचेरे भाई मिथलेश ने बताया कि चाचा पलंग में लेटे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और कांप रहे हैं। घर आकर जब वह अपने पिता से पूछताछ किया तो कुछ नहीं बताए। मां ने दो बार उल्टी करने की जानकारी दी।



आत्मानंद विद्यालय में मधुमक्खियों का हमला, 50 से अधिक बच्चे चपेट में

- 21 बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया
- बच्चों का आरोप- शिक्षकों ने बचाने के बजाय खुद को कमरों में बंद किया
- घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय घर भेजने का आरोप
- उच्च कार्यालय को घटना की सूचना नहीं देने पर भी सवाल
- परिजनों में आक्रोश, प्राचार्य को हटाने की मांग

बच्चों पर मधुमक्खियों का कहर,शिक्षक खुद को कमरों में बंद कर बचाते रहे जान!

स्कूल के बाहर मधुमक्खियों का छत्ता, प्रबंधन क्यों बना रहा अनजान?

स्कूल के बाहर मधुमक्खियों का छत्ता,प्रबंधन की लापरवाही से 50 से अधिक बच्चे चपेट में...





- मधुमक्खियों का हमला,शिक्षकों पर बच्चों को अकेला छोड़ने का आरोप,21 अस्पताल में भर्ती
- बच्चों पर मधुमक्खियों का कहर,शिक्षक खुद को कमरों में बंद कर बचाते रहे जान!
- आत्मानंद विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल,मधुमक्खियों के हमले से बच्चों में मची चीख-पुकार
- छत्ता स्कूल के बाहर,खतरे से बेखबर रहा प्रबंधन,मधुमक्खियों के हमले में दर्जनों बच्चे घायल
- मासूमों पर मधुमक्खियों का हमला,जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल...परिजनों ने मांगा प्राचार्य का हटना
- बच्चे डंक खाते रहे,प्रबंधन पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप,आत्मानंद स्कूल में गंभीर लापरवाही की जांच की मांग

-संवाददाता-

कोरिया 18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। विद्यालय को बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, अभिभावक अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों को इसी भरोसे के साथ स्कूल भेजते हैं कि वहां उनकी पढ़ाई के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की होगी,लेकिन शिवपुर चरचा स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में बुधवार दोपहर सामने आई घटना ने इस भरोसे को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, विद्यालय के ठीक बाहर मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते से निकले झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया, अचानक हुए इस हमले में प्राथमिक स्तर के 50 से अधिक बच्चों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है,जबकि 21 बच्चों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, कई अन्य बच्चे भी मधुमक्खियों के डंक से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना केवल मधुमक्खियों के हमले की कहानी नहीं है, बल्कि विद्यालय प्रबंधन की सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम, शिक्षकों की जिम्मेदारी और घटना के बाद अपनाई गई कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विद्यालय के ठीक बाहर मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद था तो उसे समय रहते हटवाने या उससे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या विद्यालय प्रबंधन को इस खतरे की जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी थी तो बच्चों को उसी रास्ते से आने-जाने क्यों दिया जा रहा था? और यदि जानकारी नहीं थी तो विद्यालय परिसर की सुरक्षा का निरीक्षण आखिर कौन कर रहा था?

छुट्टी के समय अचानक टूट पड़ा मधुमक्खियों का झुंड

जानकारी के अनुसार, शिवपुर चरचा नगर पालिका क्षेत्र का यह विद्यालय दो पालियों में संचालित होता है, बुधवार दोपहर एक पाली के विद्यार्थियों की छुट्टी हो रही थी,वहीं दूसरी पाली के विद्यार्थी विद्यालय पहुंच रहे थे, इसी दौरान विद्यालय के ठीक बाहर मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया,अचानक हुए हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई,बच्चे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, इस दौरान सबसे अधिक परेशानी प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों को हुई,जो न तो स्थिति की गंभीरता समझ पा रहे थे और न ही खुद को सुरक्षित रखने का कोई तरीका जानते थे,बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों का हमला काफी भीषण था और बड़ी संख्या में बच्चे इसकी चपेट में आ गए,बच्चों के शरीर पर कई जगह डंक लगे,घटना के बाद घायल विद्यार्थियों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया,जहां 21 बच्चों को भर्ती कर उपचार किया गया,एक विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का एक साथ घायल होना सामान्य घटना नहीं है,यह अपने आप में इस बात की मांग करता है कि पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जाए।

बच्चों का आरोप...हमारे ऊपर हमला होता रहा,शिक्षक कमरों में बंद रहे...

घटना का सबसे संवेदनशील और चिंताजनक पहलू बच्चों द्वारा लगाए गए आरोप हैं, विद्यार्थियों का कहना है कि जब मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया,तब विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें बचाने के बजाय खुद को कमरों के भीतर बंद कर लिया, छोटे-छोटे बच्चे बाहर मधुमक्खियों के बीच फंसे रहे और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे, यदि बच्चों के ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह विद्यालयीन जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा,आखिर जिन शिक्षकों के संरक्षण में बच्चे विद्यालय में रहते हैं,संकट की घड़ी में उनसे ही मदद की अपेक्षा होती है,ऐसे समय में बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, उन्हें आवश्यक सहायता दिलाने और उनकी स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? यह भी जांच का विषय है कि हमले के दौरान विद्यालय में मौजूद शिक्षकों ने बच्चों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए? क्या किसी ने तत्काल सहायता के लिए अन्य कर्मचारियों,अभिभावकों या प्रशासन को फोन किया? क्या बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया गया? या फिर बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया? इन सवालों का जवाब केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और विद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सामने आना चाहिए।

घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय घर भेजने का आरोप

बच्चों और अभिभावकों की ओर से एक और गंभीर आरोप सामने आया है,बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों के हमले के बाद जब कुछ बच्चे किसी तरह वहां से बचकर निकले तो विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने के बजाय घर भेजना शुरू कर दिया,अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों की चोट और डंक लगने की गंभीरता को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई,जब परिजनों ने अपने बच्चों की स्थिति देखी तो उन्होंने स्वयं उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाने का निर्णय लिया, यहां सवाल उठता है कि क्या विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक घायल बच्चे की स्थिति का आकलन किया था? क्या किसी शिक्षक या जिम्मेदार कर्मचारी ने बच्चों को चिकित्सकीय सहायता दिलाने की पहल की? क्या अभिभावकों को तत्काल फोन कर घटना की जानकारी दी गई? यदि बच्चे घायल थे तो उन्हें बिना चिकित्सकीय जांच के घर भेजने का निर्णय किसने लिया? मधुमक्खियों के हमले में घायल बच्चों की स्थिति को हल्के में लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता, विद्यालय प्रबंधन की पहली जिम्मेदारी यह होनी चाहिए थी कि सभी प्रभावित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती और उनके अभिभावकों को तत्काल सूचित किया जाता।

उच्च कार्यालय को सूचना क्यों नहीं दी गई?-घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठ रहा सबसे महत्वपूर्ण सवाल उच्च अधिकारियों को सूचना देने में कथित देरी का है, सूत्रों के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन ने घटना के तत्काल बाद संबंधित उच्च कार्यालय को जानकारी नहीं दी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे, यदि यह जानकारी सही है तो सवाल बेहद गंभीर है। एक विद्यालय में 50 से अधिक बच्चों के प्रभावित होने और 21 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने जैसी घटना के बाद भी संबंधित कार्यालय को समय पर सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या विद्यालय प्रबंधन ने घटना की गंभीरता को कम करके देखा? क्या मामले को दबाने या अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई? या फिर सूचना देने की व्यवस्था ही इतनी कमजोर थी कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद उच्च अधिकारी अनजान बने रहे? प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि घटना की पहली सूचना किसने दी, विद्यालय से किस समय सूचना भेजी गई और अधिकारियों को वास्तविक स्थिति की जानकारी कब मिली, यदि सूचना देने में जानबूझकर देरी की गई है तो यह अलग से जवाबदेही तय करने का विषय है।

छत्ता पहले से मौजूद था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?- इस पूरे मामले में मधुमक्खियों के छत्ते की मौजूदगी सबसे अहम सवाल बनकर सामने आई है, विद्यालय के ठीक बाहर छत्ता होने की जानकारी सामने आने के बाद यह जानना जरूरी है कि वह कितने समय से वहां मौजूद था,क्या विद्यालय प्रबंधन या शिक्षकों ने कभी इसकी सूचना नगर पालिका,वन विभाग अथवा संबंधित जिम्मेदार एजेंसी को दी थी? क्या छत्ते को हटाने के लिए कोई आवेदन या शिकायत की गई थी? यदि शिकायत की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कोई शिकायत नहीं की गई तो संभावित खतरे के बावजूद बच्चों की सुरक्षा को लेकर उदासीनता क्यों बरती गई? विद्यालय परिसर में बच्चों की आवाजाही वाले स्थानों पर मौजूद संभावित खतरों की पहचान और उनसे बचाव के इंतजाम करना प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है,मधुमक्खियों का हमला अचानक हुआ हो सकता है,लेकिन यदि छत्ता लंबे समय से मौजूद था तो उसे लेकर पहले से सावधानी बरतने की जरूरत थी,विद्यालय के प्रवेश और निकास मार्ग पर बच्चों की आवाजाही के दौरान खतरा बना हुआ था तो प्रबंधन ने वैकल्पिक रास्ते, अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था या चेतावनी जैसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि छत्ता विद्यालय की सीमा के भीतर था या बाहर, उसकी स्थिति क्या थी और उसे हटाने के लिए किस विभाग की जिम्मेदारी बनती थी, केवल यह कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता कि छत्ता विद्यालय के बाहर था, जब बच्चों की आवाजाही उसी स्थान से होती है तो सुरक्षा के प्रति सतर्कता आवश्यक थी।

प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे,लेकिन जांच और कार्रवाई का इंतजार

घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर,एसडीएम तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी जिला चिकित्सालय पहुंचे,घायल बच्चों के उपचार की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी से बच्चों के उपचार और स्थिति की जानकारी लेने की पहल जरूर हुई,लेकिन अब असली परीक्षा घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की है,जिला प्रशासन को यह जांचना चाहिए कि घटना के समय विद्यालय में कितने शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे, किसकी ड्यूटी किस कक्षा या क्षेत्र में थी,हमले के दौरान किसने क्या कदम उठाया और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में किसकी भूमिका रही,साथ ही, घटना के बाद विद्यालय की ओर से जारी की गई सूचना,अभिभावकों से संपर्क और उच्च कार्यालय को भेजे गए संदेशों का समय भी जांच के दायरे में आना चाहिए।

परिजनों में आक्रोश, प्राचार्य को हटाने की मांग...

घटना के बाद अभिभावकों में नाराजगी है,परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राचार्य को हटाने की मांग की है,उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन की ओर से अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई,अभिभावकों का यह भी आरोप है कि विद्यालय में पहले भी लापरवाही की शिकायतें सामने आती रही हैं,ऐसे में इस घटना को एक सामान्य दुर्घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए,परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, बच्चों के साथ घटना के समय मौजूद शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट की जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए,प्राचार्य को हटाने की मांग भी इसी आक्रोश का हिस्सा है, हालांकि, किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों का बयान और जांच के निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है।

आत्मानंद विद्यालय की छवि पर सवाल, बच्चों का भरोसा कौन लौटाएगा?

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों से बेहतर शिक्षा और सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है,लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के साथ बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है,यदि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चे संकट के समय खुद को असहाय महसूस करें और अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना पड़े तो यह केवल एक विद्यालय की व्यवस्था का नहीं,बल्कि पूरी निगरानी प्रणाली का सवाल बन जाता है,विद्यालय प्रबंधन को यह बताना होगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम थे? क्या परिसर और उसके आसपास नियमित निरीक्षण किया जाता था? क्या संभावित खतरे की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई थी? क्या विद्यालय में आपात स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था थी? और यदि व्यवस्था थी तो मधुमक्खियों के हमले के दौरान उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ?

अब प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना होगा, इस घटना की जांच में कम से कम इन बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए...

- विद्यालय के बाहर मधुमक्खियों का छत्ता कितने समय से मौजूद था और क्या प्रबंधन को इसकी जानकारी थी?
- छत्ता हटाने के लिए विद्यालय या नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई अथवा शिकायत की गई थी?
- हमले के समय विद्यालय में कितने शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे और उनकी जिम्मेदारी क्या थी?
- बच्चों को बचाने के लिए शिक्षकों ने क्या कदम उठाए? बच्चों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए क्या बयान दर्ज किए गए?
- घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के बजाय घर भेजने का निर्णय किसने लिया?
- अभिभावकों और उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना किस समय दी गई?
- 50 से अधिक प्रभावित बच्चों और 21 अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों की स्थिति को लेकर विद्यालय ने क्या रिकॉर्ड तैयार किया?
- क्या विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद थी?

CMYK



बॉलीवुड में दो नए स्टारकिड की एंट्री

साजिद नाडियाडवाला के बेटे और रोहित रॉय की बेटी पर्दे पर लड़ाएंगे इश्क,
'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं का हुआ ऐलान

फिल्ममेकर शशांक खेतान की नई रोमांटिक रिवेंज फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' से सुभान और ऐराह बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। फिल्म में प्यार, जुनून और बदले की कहानी देखने को मिलेगी।

बॉलीवुड में एक नई रोमांटिक जोड़ी दस्तक देने जा रही है। फिल्ममेकर शशांक खेतान अपनी अगली फिल्म ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं% के साथ एक बार फिर प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा अलग होगा। फिल्म में निर्माता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा नाडियाडवाला के बेटे सुभान बतौर लीड एक्टर डेब्यू करेंगे। उनके साथ रोहित रॉय और मानसी जोशी रॉय की बेटी कीआरा बोस रॉय नजर आएंगी, जिन्हें पर्दे पर ऐराह के नाम से पेश किया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो जारी कर इसकी पहली झलक दिखाई है।

रोमांस के साथ बदले की कहानी,
खून से सने नजर आए नए कलाकार

फिल्म के टाइटल रिवील वीडियो में सुभान और ऐराह एक-दूसरे की बाहों में नजर आते हैं। दोनों के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान हैं और इस हालत में भी वे एक-दूसरे को किस करते दिखाई देते हैं। वीडियो की शुरुआत रोमांटिक अंदाज में होती है, लेकिन आगे बढ़ते-बढ़ते कहानी में एक गहरा और हिंसक मोड़ आने का संकेत मिलता है। मेकर्स ने इसे रोमांटिक रिवेंज ड्रामा बताया है, जिसमें प्यार, जुनून और बदले की भावना अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि फिल्म की कहानी और किरदारों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। फिल्म के पोस्ट के साथ मेकर्स ने लिखा,ये दीवाने हैं कुछ और तरह के...कुछ और तरह की दीवानगी... इस टैगलाइन से साफ है कि फिल्म में इश्क की एक अलग और जुनूनी दुनिया देखने को मिल सकती है।

दिव्या भारती के गाने से जुड़ा है फिल्म का नाम

फिल्म के टाइटल ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं का भी एक खास कनेक्शन है। यह गाना दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की फिल्म दीवाना का हिस्सा था। साल 1992 में रिलीज हुई इस फिल्म से शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कदम रखा था। ऐसे में फिल्म का यह नाम पुराने हिंदी सिनेमा की यादें भी ताजा करता है। हालांकि, फिल्म की कहानी और इस टाइटल के बीच क्या संबंध होगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।

शशांक खेतान के नए प्रोडक्शन बैनर के तहत बन रही फिल्म

ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं शशांक खेतान के लिए एक और वजह से खास है। यह उनके नए प्रोडक्शन बैनर 214 एंटरटेनमेंट के तहत बनने वाली फिल्मों में शामिल है। इस बैनर की स्थापना शशांक खेतान, अमित चंद्रा और नलिनी दत्ता खेतान ने की है। फिल्म का निर्माण शशांक, अमित चंद्रा, नलिनी दत्ता खेतान और करिश्मा ठक्कर मिलकर कर रहे हैं। शशांक ने ही इसकी कहानी लिखने के साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। फिल्म के संगीत को भी खास बनाने की तैयारी है। इसका म्यूजिक टी-सीरीज रिलीज करेगी। वहीं अमाल मलिक फिल्म के गानों को कंपोज करने के साथ अपनी आवाज भी देंगे।

दीया मिर्जा के 'बदतमीज' कहने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया पलटवार

लेकिन फैंस को लग रहा दाल में कुछ काला

दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बदतमीज बताते हुए निशाना साधा, जिस पर अभिनेता ने भी जवाब दिया। दोनों की यह नोकझोंक उनकी आगामी सीरीज डॉ. हसन के प्रमोशन से जुड़ी मानी जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज डॉ. हसन को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि,इस बार दोनों अपनी सीरीज की कहानी या किरदारों की वजह से नहीं,बल्कि सोशल मीडिया पर हुई एक दिलचस्प बातचीत को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दीया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। अभिनेत्री ने अभिनेता के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्हें काम करने के लिहाज से बेहद मुश्किल बताया। इसके बाद नवाजुद्दीन ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया।

दीया मिर्जा ने
नवाजुद्दीन को लेकर क्या लिखा?

दरअसल दीया मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए लिखा,इनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है। बात करने की तमीज नहीं है और एटीट्यूड तो अलग ही लेवल का है। बिल्कुल आपत्तिजनक किरदार। अभिनेत्री के इस संदेश ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। पहली नजर में उनका यह बयान नवाजुद्दीन की आलोचना जैसा लगा। हालांकि पोस्ट में इस्तेमाल किए गए किरदार शब्द ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह दोनों की



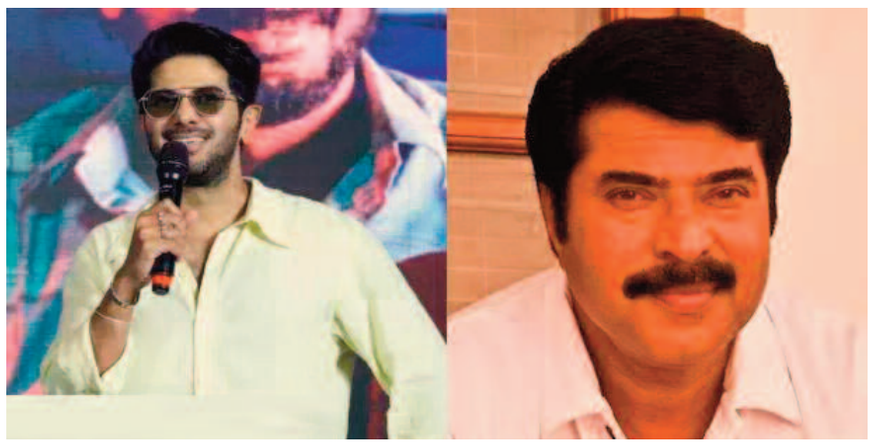
आने वाली सीरीज के प्रमोशन का हिस्सा तो नहीं है। दरअसल दीया ने अपने पोस्ट में अभिनेता को टैग भी किया था,जिसके बाद फैंस यह समझने की कोशिश करने लगे कि उनके बीच वास्तव में कोई विवाद हुआ है या फिर यह नए प्रोजेक्ट को लेकर अपनाई गई प्रमोशनल रणनीति है।

नवाजुद्दीन ने भी दिया जवाब,
कमेंट ने बढ़ाई चर्चा

दीया की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कई लोगों ने इसे सीरीज के प्रचार का नया तरीका बताया। एक यूजर ने लिखा कि यहां किरदार शब्द पर ध्यान देना चाहिए, जल्द ही दोनों के साथ किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरे यूजर ने सीधे सवाल किया कि क्या यह पीआर स्टंट है? कुछ लोगों ने लिखा कि दोनों कलाकार काफी प्रोफेशनल हैं और ऐसा व्यवहार उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता। एक अन्य यूजर ने भी इसे प्रमोशन का हिस्सा बताते हुए लोगों को शांत रहने की सलाह दी। इस बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी दीया की पोस्ट पर कमेंट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने लिखा,एटीट्यूड में कमी निकालना आसान है, काम में निकालकर दिखाइए। नवाजुद्दीन के इस जवाब ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को और हवा दे दी। अब फैंस दोनों के बीच हुई इस बातचीत को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं। हालांकि दोनों कलाकारों ने इसे लेकर किसी वास्तविक विवाद की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

क्या है दीया और नवाजुद्दीन की डॉ हसन?

बता दें कि दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही मेडिकल ड्रामा सीरीज डॉ. हसन में साथ नजर आने वाले हैं। इस सीरीज का निर्देशन रोहन सिप्पी कर रहे हैं। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी डॉ. इमरान हसन और दीया मिर्जा डॉ. पलक जैन की भूमिका निभा रही हैं। इनके अलावा फैसल राशिद भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। वह सीरीज में डॉ विवेक भार्गव का रोल निभा रहे हैं,जो एक बेहद प्रतिभाशाली लेकिन असामान्य व्यक्तित्व वाले डॉक्टर हैं। सीरीज की कहानी एक ऐसे जीनियस डॉक्टर और उनकी विशेषज्ञ मेडिकल टीम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जटिल मेडिकल मामलों को सुलझाने का काम करते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी निजी जिंदगी की चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। मेडिकल रहस्यों, डॉक्टरों के आपसी रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों को मिलाकर यह कहानी तैयार की गई है। डॉ. हसन का प्रीमियर 27 दिसंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर होने वाला है। ऐसे में दीया और नवाजुद्दीन की सोशल मीडिया पर हुई इस बातचीत को सीरीज के प्रमोशन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की यह नोकझोंक दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर कितनी उत्सुकता बढ़ाती है।



रिलीज से पहले ही फिल्मों की जीत तय!

मलयालम स्टार दुलकीर सलमान की आने वाली तेलुगु फिल्म आकासमलो ओका तारा और उनके पिता ममूटी की तमिल फिल्म ओम 20 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। इस पर दुलकीर ने मज़ाक में कहा कि उनकी माँ उनका पक्ष लेंगी और अपने पति (ममूटी) की फिल्म देखने से पहले उनकी (दुलकीर की) फिल्म देखेंगी। मंगलवार को चेन्नई में निर्देशक पवन सदिनेनी की आने वाली फिल्म आकासमलो ओका तारा के प्री-रिलीज़ इवेंट में दुलकीर सलमान शामिल हुए। इस दौरान, अभिनेता को बताया गया कि उनकी और उनके पिता की फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हो रही हैं। उनसे पूछा गया कि क्या 20 नवंबर को कड़ा मुकाबला होगा और उनकी माँ सबसे पहले किसकी फिल्म देखेंगी। मुस्कुराते हुए दुलकीर ने इस बात पर खुशी जताई और मज़ाक में कहा कि उनकी माँ का झुकाव शायद उनकी तरफ ही होगा। उन्होंने कहा,मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि मैं इतने सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ,लेकिन उन्होंने कभी मेरी फिल्मों के बारे में इस तरह सवाल नहीं पूछे और न ही मेरी फिल्में उस तरह देखीं,जैसे तुम्हारी फिल्में देखती हैं। तुम्हारे आने के बाद से,वह तुम्हारी सारी फिल्में देखती हैं। गंभीर होते हुए अभिनेता ने कहा कि यह वाकई एक आशीर्वाद की बात है। उन्होंने आगे बताया,हम दोनों मलयाली अभिनेता हैं। मेरी फिल्म एक शुद्ध तेलुगु फिल्म है,जबकि मेरे पिता की फिल्म ओम एक शुद्ध तमिल फिल्म है। मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए बहुत खुशी का पल है।

अर्थशॉट प्राइज़ में आलिया भट्ट का लुक ट्रोल,'चिपके हुए जूड़े' पर मचा बवाल

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट एक बार फिर अपने रेड कार्पेट लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। मुंबई में आयोजित 'अर्थशॉट प्राइज़ 2026' समारोह में आलिया भट्ट ने ब्लैक एंड गोल्ड आउटफिट में शिरकत की, लेकिन इस बार उनके कपड़ों से ज्यादा उनके हेयरस्टाइल ने लोगों का ध्यान खींचा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके स्लीक,टाइट जूड़े यानी 'चिपके हुए बन' को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि यह हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक को कमजोर कर गया। कुछ फैंस ने तो एआई जनरेटेड तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें आलिया को अलग-अलग हेयरस्टाइल में दिखाया गया और दावा किया गया कि खुले बाल, सॉफ्ट कलर्स या ब्रेडेड स्टाइल में उनका लुक कहीं ज्यादा बेहतर लग सकता था। अर्थशॉट प्राइज़ 2026 का आयोजन मुंबई में हुआ,जहां देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। आलिया भट्ट ने इस मौके पर ब्लैक एंड गोल्ड रंग का स्ट्रैपलेस, एम्ब्रॉयडर्ड गाउन पहना था। उनके आउटफिट में सुनहरे कढ़ाईदार डिटेलिंग थी,जिसे उन्होंने स्टेटमेंट गोल्ड इयररिंग्स और स्लीक बन के साथ पूरा किया। पहली नजर में उनका लुक ग्लैमरस और हाई-फैशन दिखाई दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रेडिट पर कई यूजर्स ने आलिया के हेयरस्टाइल और मेकअप पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का कहना था कि उनका जूड़ा बहुत ज्यादा टाइट था,जिससे चेहरा और आंखों का लुक प्रभावित हो रहा था। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि आंखों का मेकअप और हेयरस्टाइल मिलकर उनके चेहरे को जरूरत से ज्यादा कड़ा लुक दे रहे थे। कई लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि इस चिपके हुए जूड़े के ट्रेंड को खत्म कर देना चाहिए।



खेल-समाचार

भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला आज

बेसिन रिजर्व में 8 टेस्ट मैच खेल चुकी टीम इंडिया, 58 साल पुराना सूखा खत्म करने की चुनौती

वेलिंगटन,18 नवम्बर 2026। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए बेताब भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार के दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। दोनों ही टीमों की टक्कर वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में होगा। भारत को यहां की हवादार और तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही परिस्थितियों में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। इसमें कप्तान शुभमन गिल की रणनीतिक सूझबूझ और दबाव झेलने की क्षमता की भी परीक्षा होगी।

भारत का वेलिंगटन में
रिकॉर्ड साधारण

बेसिन रिजर्व के मैदान पर टीम इंडिया का टेस्ट में रिकॉर्ड काफी साधारण है। टीम ने यहां 1968 में अपना पहला मुकाबला खेला था। उसमें 8 विकेट से जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद से हुए 7 टेस्ट मैचों में भारत एक भी अपने नाम नहीं कर पाया



है। न्यूजीलैंड को 5 जीत मिली है वहीं दो मैच ड्रॉ रहे हैं। 2020 के पिछले दौरे पर भारत ने यहां टेस्ट मैच खेला था। न्यूजीलैंड को उसमें 10 विकेट से जीत मिली थी।

आखिरी टेस्ट की दोनों
पारियों में बैटिंग फेल रही

2020 में यहां हुए आखिरी टेस्ट में की दोनों ही पारियों में भारतीय टीम 200 रनों तक नहीं पहुंच पाई थी। विराट कोहली की कप्तानी में टीम पहली पारी में 165 रनों पर सिमट गई थी। टिम साउदी और काइल जेमिसन ने 4-4 विकेट झटके थे। दूसरी पारी में टीम ने 191 रन बनाए थे। इस पारी में साउदी ने 5 और बोल्ट ने 4 विकेट लिए थे। साउदी और बोल्ट दोनों टीम में नहीं हैं लेकिन मैट हेनरी के रूप में न्यूजीलैंड के पास खतरनाक पेसर है।

टीम इस प्रकार हैं

भारतः शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा,मोहम्मद सराज,साई सुदर्शन,गुरनूर बरार,वाशिंगटन सुंदर।

न्यूजीलैंडः टॉम लाथम (कप्तान), रचिन रविंद्र, विल यंग,ग्लेन फिलिप्स,डैरिल मिचेल,टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर),डीन फॉक्सक्रॉफ्ट,जैकब डफी,मैट हेनरी, काइल जैमीसन,नाथन स्मिथ,ब्लेयर टिकनर,हेनरी निकोल्स,डेवोन कॉन्वे।



वर्ल्ड टेनिस लीग में सितारों का जमावड़ा, किर्गियोस समेत 16 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

बेंगलुरु,18 नवम्बर 2026। वर्ल्ड टेनिस लीग के पांचवें सीजन के लिए दुनिया के दिग्गज और उभरते टेनिस खिलाड़ियों की शानदार लाइनअप की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2026 तक बेंगलुरु के केएसएलटीए एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में किया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 16 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे,जिनमें आठ अंतरराष्ट्रीय और आठ भारतीय टेनिस खिलाड़ी शामिल हैं। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेन्सिक,चेक गणराज्य की करोलिना प्लिस्कोवा, ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा प्रतियोगिता के प्रमुख आकर्षण होंगे। आयोजकों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय चैंपियन और युवा भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी से इस बार मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।वर्ल्ड टेनिस लीग के पांचवें सीजन में चार टीमें भाग लेंगी। इनमें एक्रिक्स इंगल्स,गेम चेंजर्स फाल्कन्स,ऑसी मावेरिक्स काइट्स और वीबी रियल्टी हॉक्स शामिल हैं। इन टीमों में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भारतीय टेनिस प्रतिभाओं को भी खेलने का अवसर मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना और भारतीय दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले देखने का अवसर प्रदान करना है।

आईपीएल 2027 की नीलामी का ऐलान
16 दिसंबर को गोवा में लगेगी बोली

नई दिल्ली,18 नवम्बर 2026। इंडियन प्रीमियर लीग 2027 की नीलामी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुष्टि कर दी है कि आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2026 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है। इस बार टीमों ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है,जबकि हार्दिक पांड्या,अर्शदीप सिंह,ऋषभ पंत और कुलदीप यादव जैसे भारतीय सितारों की टीमें ट्रेड के जरिए बदल गई हैं। बीसीसीआई के अनुसार, सभी फ्रेंचाइजी ने कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन किया है,जबकि 89 खिलाड़ियों को



रिलीज किया गया है। अब नीलामी में टीमें अपने बचे हुए बजट के अनुसार नए खिलाड़ियों को खरीद सकेंगी।

16 दिसंबर को गोवा में होगा
आईपीएल मिनी ऑक्शन

बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, आईपीएल 2027 की खिलाड़ियों की नीलामी बुधवार, 16 दिसंबर 2026 को गोवा के आईटीसी ग्रैंड होटल में आयोजित होगी।नीलामी भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान सभी 10 फ्रेंचाइजी अपने खाली स्थान भरने के लिए खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी।आईपीएल 2027 का यह 20 वां संस्करण होगा। ऐसे में आगामी सीजन को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह बना हुआ हैबीसीसीआई ने पहले रिटेंशन लिस्ट जारी करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर निर्धारित की थी। बाद में इसे दो दिन बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सुरजीत (माता/पिता / पालक का नाम) सुपुत्र / सुपुत्री मनोहर मानिकपुरी गॉव / शहर निवासी बुलंगा पोस्ट उदारी, तह0 लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र / सुपुत्री का नाम नीरज मानिकपुरी (NIRAJ MANIKPURI) (पुराना नाम) से बदल कर नीरज कुमार (NIRAJ KUMAR) (नया नाम) रख लिया हैं।

शपथकर्ता
सुरजीत
माता/पिता / पालक के हस्ताक्षर

नाम परिवर्तन सूचना

मै सोनामती पति श्री दिनेश सिंह उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम कुंजनगर पोस्ट जयनगर थाना जयनगर तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ0ग0) शपथ पूर्वक कथन करती हूं कि मेरा सही व वास्तविक नाम गायत्री (GAYATRI SINGH) पति दिनेश सिंह है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र एंव बैंक पासबुक में दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सोनामती दर्ज है जो कि गलत है।

अतः आज से मुझे मरे वास्तविक नाम नाम गायत्री सिंह (GAYATRI SINGH) पति दिनेश सिंह के नाम से जाना पहचाना एवं समस्त दस्तावेज में दर्ज किया जाए । इस संबंध में मेरा मेरा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

शपथकर्ता
गायत्री
सोनामती (SONAMATI)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं विनेशदेवी राजवाड़े पति श्री जान साय उम्र लगभग 52 वर्ष निवासीग्राम- कैलाशपुर, पोस्ट-जयनगर, तहसील- लटोरी, जिला-सूरजपुर (छ.ग) नम्नांकित शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा सही व वास्तविक नाम विनेश कुमारी (VINESH KUMARI) पति श्री जान साय है जो कि सही है। जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विनेशदेवी राजवाडे (VINESHDEVI RAJWADE) दर्ज है जो कि गलत है।

अतः आज से मुझे मेरा वास्तविक नाम विनेश कुमारी (VINESH KUMARI) पति श्री जान साय के नाम से जाना पहचाना एवं समस्त दस्तावेज में दर्ज किया जाए। इस संबंध में मेरा मेरा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

शपथकर्ता.
विनेशदेवी राजवाड़े

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/s Maa Durga Traders में दिनांक 01 अक्टूबर 2026 से श्रीमती Beauti Bacchad फर्म की साझेदार (Partner) नहीं रहेंगी।

अतः उक्त दिनांक से फर्म के व्यवसाय, लेन-देन, वित्तीय एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उनका कोई संबंध नहीं रहेगा तथा उक्त तिथि के पश्चात फर्म की ओर से किए जाने वाले किसी भी कार्य, लेन-देन अथवा दायित्व के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगी।

इस संबंध में सभी संबंधित व्यक्ति,संस्थान,बैंक,व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं अन्य पक्षकार कृपया उक्त परिवर्तन को अपने अभिलेखों में दर्ज कर लें तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार वर्तमान अधिकृत साझेदारों के माध्यम से ही करें।

सूचनाकर्ता
समस्त वर्तमान साझेदार
M/s Maa Durga Traders

CMYK



फरार शोएब ढेबर से कथित सांठगांठ के आरोप में निरीक्षक विनीत दुबे निलंबित

- तेलीबांधा थाने के अपराध क्रमांक 403/2026 में संदिग्ध आचरण बना कार्रवाई का आधार
- रायपुर पुलिस कमिश्नर के 30 अक्टूबर के प्रतिवेदन पर बस्तर आईजी बदी नारायण मीणा ने 16 नवंबर को जारी किया आदेश
- गोपनीय कार्रवाई की जानकारी लीक होने का संदेह, पहले ही दो आरक्षक हो चुके हैं निलंबित
- अंबिकापुर के कस्तूरियन डेथ और कोरिया के जमीन विवाद सहित कई मामलों में पहले भी चर्चा में रहा है नाम

25 करोड़ की उगाही कांड में पुलिस महकमे पर गिरी गाज,निरीक्षक विनीत दुबे निलंबित....

गोपनीय कार्रवाई की जानकारी लीक होने का संदेह, अब निरीक्षक विनीत दुबे पर निलंबन की कार्रवाई

दो आरक्षकों के बाद अब निरीक्षक पर कार्रवाई,शोएब ढेबर प्रकरण में पुलिस महकमे की बढ़ी मुश्किलें

विवादों से पुराना नाता,अब फरार शोएब ढेबर प्रकरण में निरीक्षक विनीत दुबे निलंबित

अंबिकापुर के कस्तूरियन डेथ प्रकरण से लेकर कोरिया के जमीन विवाद तक पुराने मामलों को लेकर भी चर्चा में रहा है नाम

-दुलारे अंसारी-

रायपुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कानून की रक्षा करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी जिन पुलिस अधिकारियों के कंधों पर होती है, जब उन्हीं अधिकारियों का आचरण विभागीय जांच के दायरे में आने लगे तो सवाल केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहते,बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर खड़े होने लगते हैं,छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बार फिर ऐसा ही मामला चर्चा में है,फरार आरोपी शोएब ढेबर से कथित सांठगांठ और पुलिस की गोपनीय कार्रवाई की जानकारी लीक होने के संदेह के बीच निरीक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर दिया गया है,बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बदी नारायण मीणा ने 16 नवंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया,यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा 30 अक्टूबर को भेजे गए प्रतिवेदन और प्रारंभिक जांच से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर की गई है, इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे के भीतर हलचल पैदा कर दी है,वजह यह है कि मामला किसी सामान्य विभागीय लापरवाही का नहीं,बल्कि एक ऐसे प्रकरण से जुड़ा है जिसमें पुलिस की गोपनीय गिरफ्तारी योजना की जानकारी आरोपी तक पहुंचने की आशंका सामने आई थी,पुलिस टीम दबिश देने पहुंचती रही और आरोपी के पहले ही निकल जाने की घटनाओं ने विभाग के भीतर सूचना के स्रोत और संभावित लीक को लेकर संदेह पैदा किया,पहले दो आरक्षकों पर कार्रवाई हुई और अब निरीक्षक स्तर के अधिकारी का निलंबन इस मामले को और गंभीर बना रहा है।

25 करोड़ की कथित रंगदारी का मामला,गिरफ्तारी से पहले कैसे लीक हुई सूचना?

पूरा मामला कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है,इस प्रकरण में शोएब ढेबर आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, बताया गया कि पुलिस ने न्यायालय से अनुमति लेकर उसके संभावित ठिकानों पर एक साथ दबिश देने की योजना तैयार की थी, इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था,ताकि आरोपी को पुलिस की गतिविधियों की जानकारी न मिल सके,लेकिन 3 अक्टूबर को सामने आए घटनाक्रम ने पुलिस की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए,खम्हारडीह इलाके में पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही शोएब ढेबर के वहां से निकल जाने की बात सामने आई,अन्य संभावित ठिकानों पर भी दबिश के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी,इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर पुलिस की गोपनीय योजना की जानकारी आरोपी तक कैसे पहुंची? किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की रणनीति और संभावित ठिकानों की जानकारी अत्यंत संवेदनशील होती है,यदि ऐसी जानकारी समय से पहले आरोपी तक पहुंच जाए तो पुलिस की पूरी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है, यही वजह है कि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग के भीतर सूचना लीक होने की आशंका को गंभीरता से लिया गया।

कानून के रक्षक की भूमिका पर सवाल, विभागीय मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण?

पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं,बल्कि जिम्मेदारी,अनुशासन और जनता के विश्वास का प्रतीक भी है, आम नागरिक पुलिस से अपेक्षा करता है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निष्पक्ष होगी और कानून का पालन सबसे पहले पुलिसकर्मी स्वयं करेंगे,ऐसे में यदि किसी पुलिस अधिकारी के आचरण पर संदिग्ध होने का विभागीय निष्कर्ष सामने आता है तो यह स्वाभाविक रूप से गंभीर चिंता का विषय बनता है,पुलिस के पास अपराधियों की गतिविधियों,उनके संपर्कों और गिरफ्तारी की योजनाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारी होती है,इस जानकारी की सुरक्षा करना विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है,यदि गोपनीय सूचनाएं बाहर पहुंचती हैं तो इससे न केवल पुलिस की कार्रवाई प्रभावित होती है,बल्कि अपराधियों का मनोबल भी बढ़ सकता है,इसलिए इस प्रकरण में केवल निलंबन पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि सूचना लीक होने की पूरी कड़ी का पता लगाना आवश्यक है।

निलंबन आदेश में क्या कहा गया?

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी 16 नवंबर 2026 के आदेश में रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 403/2026 का उल्लेख किया गया है, यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 351(3) और 351(4) से संबंधित है, आदेश के अनुसार रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 30 अक्टूबर 2026 को पत्र क्रमांक पुलिस कमिश्नर/राय./ स्टेनो/ 469/ 2026 के माध्यम से प्रतिवेदन भेजा था, इस प्रतिवेदन और संलग्न प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर निरीक्षक विनीत दुबे का आचरण संदिग्ध तथा विभागीय मर्यादा के प्रतिकूल पाए जाने का उल्लेख करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, नारायणपुर निर्धारित किया गया है, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा,आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर,पुलिस कमिश्नर रायपुर और पुलिस अधीक्षक नारायणपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है,यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निलंबन आदेश में शोएब ढेबर के साथ कथित सांठगांठ का पूरा घटनाक्रम विस्तार से दर्ज नहीं है,आदेश में मुख्य रूप से रायपुर पुलिस कमिश्नर के प्रतिवेदन और निरीक्षक के संदिग्ध आचरण का उल्लेख है,इसलिए निलंबन को आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता,वास्तविक भूमिका और जिम्मेदारी विभागीय जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।

पहले दो आरक्षक निलंबित, अब निरीक्षक पर कार्रवाई...

गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में इससे पहले एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में पदस्थ आरक्षक शिवम द्विवेदी और राहुल सिंह गौतम को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है,दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे,ताकि यह पता लगाया जा सके कि संवेदनशील कार्रवाई की जानकारी बाहर पहुंचने में उनकी कोई भूमिका थी या नहीं,अब निरीक्षक विनीत दुबे पर कार्रवाई ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, सवाल यह है कि क्या गोपनीय सूचना लीक होने की घटना में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की भूमिका थी या विभाग के भीतर अन्य स्तरों पर भी जानकारी साझा हुई थी? क्या पुलिस की कार्रवाई से संबंधित सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच थी? क्या किसी ने जानबूझकर आरोपी को सतर्क किया? इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है,लगातार तीन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई यह बताती है कि पुलिस कमिश्नरेट इस प्रकरण को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन कार्रवाई के साथ यह भी जरूरी है कि जांच का दायरा स्पष्ट हो और यह पता लगाया जाए कि गोपनीय जानकारी बाहर जाने की वास्तविक वजह क्या थी।

जांच में इन सवालों का जवाब जरूरी इस पूरे मामले में अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब सामने आना चाहिए...

- शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई गोपनीय योजना की जानकारी आरोपी तक कैसे पहुंची?
- खम्हारडीह में पुलिस दबिश से पहले आरोपी के निकल जाने के पीछे क्या कारण था?
- प्रारंभिक जांच में निरीक्षक विनीत दुबे का आचरण किन तथ्यों के आधार पर संदिग्ध पाया गया?
- निलंबित आरक्षकों और निरीक्षक के बीच कोई संपर्क या सूचना साझा होने का प्रमाण मिला है या नहीं?
- क्या पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है?
- पूर्व में विनीत दुबे से जुड़े बताए जा रहे विवादों में कोई विभागीय जांच हुई थी या नहीं?

निलंबन के बाद अब जांच के निष्कर्ष पर टिकी निगाहें- फिलहाल निरीक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर उनका मुख्यालय नारायणपुर निर्धारित कर दिया गया है, विभागीय जांच के दौरान उनके आचरण और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी है,साथ ही फरार शोएब ढेबर की गिरफ्तारी और कथित रंगदारी के मामले की जांच भी महत्वपूर्ण बनी हुई है,यह मामला केवल एक निरीक्षक के निलंबन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि पुलिस की गोपनीय कार्रवाई की जानकारी वास्तव में विभाग के भीतर से लीक हुई है तो यह गंभीर संस्थागत चूक है, इसकी पूरी कड़ी सामने आनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए,उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए,कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था में यदि गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रह पाए तो अपराधियों तक कानून का शिकंजा कैसे पहुंचेगा? विनीत दुबे के निलंबन ने यह सवाल एक बार फिर सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच केवल निलंबन तक सीमित रहती है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपी वास्तविक भूमिका और जिम्मेदारी भी सामने लाई जाती है।

विनीत दुबे का नाम पहले भी विवादों में आने का दावा

निरीक्षक विनीत दुबे का नाम केवल इस ताजा कार्रवाई के कारण ही चर्चा में नहीं आया है,उनके पूर्व कार्यकाल और पुराने विवादों को लेकर भी क्षेत्र में सवाल उठते रहे हैं,अंबिकापुर के चर्चित कस्तूरियन डेथ प्रकरण और कोरिया जिले में जमीन पर कब्जे से जुड़े विवादों के संदर्भ में भी उनका नाम चर्चा में आने की बात कही जाती रही है,इन पुराने मामलों को लेकर यह सवाल भी उठता रहा है कि पुलिस अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई करना है,लेकिन यदि किसी अधिकारी का नाम बार-बार विवादों में आने लगे तो विभागीय स्तर पर उसकी कार्यशैली की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या पुराने मामलों में भी कोई शिकायत या विभागीय जांच हुई थी? यदि हुई थी तो उसका निष्कर्ष क्या रहा? क्या उन मामलों में अधिकारी की भूमिका की जांच की गई थी? लेकिन यदि इन मामलों को लेकर शिकायतें या अभिलेख मौजूद हैं तो विभाग को उनकी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, किसी अधिकारी के विरुद्ध उठने वाले सवालों का समाधान केवल चुप्पी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और स्पष्ट निष्कर्ष से होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से...टाइम-टेबल जारी,8 अप्रैल तक एग्जाम,हिंदी से शुरुआत होगी

-संवाददाता-

रायपुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगी। वहीं, 10वीं की परीक्षा 13 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। 12वीं की पहली परीक्षा हिंदी की होगी, जबकि 10वीं के स्टूडेंट्स को पहले दिन तीसरी भाषा का पेपर देना होगा। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक होंगे। मंडल ने फिजिकल ट्रेनिंग डिप्लोमा परीक्षा की समय-सारणी भी जारी की है। यह परीक्षा 12 से 20 मार्च तक होगी।

12वीं में 12 मार्च को हिन्दी और 31 मार्च को अंग्रेजी का पेपर : हायर सेकंडरी मुख्य परीक्षा में 12 मार्च को हिंदी, 15 मार्च को राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र और लेखा शास्त्र की परीक्षा होगी।

17 मार्च को संस्कृत, 19 मार्च को जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र का पेपर होगा। इसके बाद 24 मार्च को समाजशास्त्र, 29 मार्च को गणित और कम्प्यूटर एप्लीकेशन, जबकि 31 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। अप्रैल में 3 तारीख को इतिहास और बिजनेस स्टडीज, 5 अप्रैल को भूगोल और फिजिक्स और 8 अप्रैल को साइकोलॉजी का पेपर होगा।



10वीं में 20 मार्च को विज्ञान और 30 मार्च को गणित : हाईस्कूल परीक्षा की शुरुआत 13 मार्च को तीसरी भाषा के पेपर से होगी। इसमें संस्कृत, मराठी, उर्दू सहित अन्य भाषाएं शामिल हैं। 16 मार्च को अंग्रेजी, 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान और 20 मार्च को विज्ञान की परीक्षा होगी।

इसके बाद 25 मार्च को हिंदी और 30 मार्च को गणित का पेपर होगा। 1 अप्रैल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा होगी। इनमें रिटेल, आईटी और हेल्थ केयर जैसे विषय शामिल हैं। 5 अप्रैल को दृष्टिहीन और मूक-बधिर विद्यार्थियों के विशेष विषयों की परीक्षा होगी।

सुबह 9:15 बजे से लिख सकेंगे उत्तर : मंडल के निर्देश के मुताबिक परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सुबह 9:05 बजे उत्तर पुस्तिकाएं और 9:10 बजे प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे। इसके बाद 9:15 बजे से उत्तर लिखना शुरू होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले निर्धारित समय पर केंद्र में पहुंचना अनिवार्य होगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)